CNEWS सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-269
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, शुक्रवार 03 जनवरी 2025

आज का विचार

सफल मनुष्य वही है जो सभी के हितों का ध्यान रखता है.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया साफ की हर बात- यूनियन कार्बाइड के कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से हो रहा निष्पादन, आशंकाएं निर्मूल, डरने की जरूरत नहीं

इंदौर-भोपाल। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर जनता में डर है, लेकिन मप्र सरकार ने इसे निपटाने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण और जांच के बाद उसे सुरक्षित बताया है। कचरे में कोई हानिकारक तत्व नहीं हैं और इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के 337 टन विषैले कचरेके निष्पादन को लेकर उठ रही आशंकाएं निर्मूल हैं। भोपाल के लोग 40 वर्षों से इसी कचरे के साथ रहते आए हैं इसलिए कांग्रेस या जो लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं उन्हें इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के 358 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार निष्पादन पीथमपुर में किया जा रहा है। इस कचरे में 60 प्रतिशत मिट्टी और 40 प्रतिशत 7 नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। उन्होंने आगे बताया कि कीटनाशक बनाने में नेफ्थाल सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका असर 25 वर्षों में समाप्त हो जाता है। चूंकि घटना को 40 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए कचरे के निष्पादन को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो स्वत समाप्त हो जाती हैं।

गहन अध्ययन, परीक्षण के बाद तय हुई प्रक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि कचरे के निष्पादन के लिए कई संस्थाओं ने गहन अध्ययन और परीक्षण किया। कोर्ट और कई विभागों के सुझाव और परामर्श के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद, आईआईसीटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन और उनकी रिपोर्ट के बाद कचरा निष्पादन प्रक्रिया तय हुई। इससे पहले 2013 में केरल के कोच्ची के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर इसे पीथमपुर में जलाकर परीक्षण किया जा चुका है। इसे सफलता के साथ जलाकर इसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। सभी निष्कर्षों की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि कचरे के निष्पादन से किसी प्रकार वातावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया की अनुमति दी। फैक्टरी के बाहर के कचरे का भी निष्पादन किया जाएगा इसीलिए भोपाल की 40 साल पुरानी समस्या का अब समाधान हो रहा है।

सबको भरोसे में साथ लेकर आगे बढ़ रहे सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी पारदर्शिता के साथ रख रहे हैं। इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धार में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर उन्हें विश्वास में लेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि फैक्टरी के बाहर के कचरे का भी भविष्य में निष्पादन किया जाएगा।

जमीन में नहीं जा पाएगा कचरा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अपशिष्ट पदार्थ को जलाने के पहले फैक्ट्री के नीचे सीमेंट कंक्रीट का प्लेटफार्म बनाया गया है। साथ ही इसको जलाने के बाद जो राख निकलेगी, उसे भी कंटेनर में भरकर रखा जाएगा। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नीचे कंक्रीट होगा, तो फिर जमीन में पानी कैसे जाएगा। कांग्रेस के आकाओं के दौर में भोपाल में लोगों के मरने के लिए इसमें पानी पहुंचाया गया था, जो यह सवाल उठा रहे हैं, उनके पाप के किस्से भी बताने पड़ेंगे। उनके शासन काम में ही यह फैक्टरी चल रही थी और उसके 20 साल बाद भी कुछ नहीं किया। वे अब पीथमपुर में विरोध कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में आकर कुछ बात नहीं करते। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक चश्मे के कारण लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उनको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। उधर यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में अन्य स्थानों पर पड़े कचरे को लेकर मुख्यमंत्री से जब सवाल किया गया कि बाकी कचरे का क्या होगा ? जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ उसके बारे में बता दिया जाएगा।

तत्कालीन सरकार ने गैस पीड़ितों के साथ निष्ठुर व्यवहार किया सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया कि 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात मैं भोपाल ही था। उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थी परिषद की बैठक में शामिल होने आए थे। उन्होंने बताया कि भोपाल का वो दृश्य दर्दनाक था, लेकिन उसके बाद तत्कालीन सरकार ने गैस पीड़ितों के साथ निष्ठुर व्यवहार किया।

कांग्रेस दोमुंही बात न करे सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि हादसे के बाद कांग्रेस की 20 साल तक सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस समस्या को लेकर कुछ नहीं किया। कांग्रेस केवल दो मुही राजनीती कर रही है, इन्हें भोपाल वासियों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस दो मुंही बात न करे।

इसलिए डरने की जरूरत नहीं...

-कचरे में 60 प्रतिशत स्थानीय मिट्टी और 40 प्रतिशत 7-नेफ्थाल, रिएक्टर रेसिड्यू और प्रोसेस पेस्टीसाइड्स का अपशिष्ट है।

-नेफ्थाल रिएक्टर रेसिड्यू का जहरीलापन 25 साल में समाप्त हो जाता है, और इस समय तक कचरे में कोई हानिकारक तत्व नहीं हैं।

-कचरा निपटान की प्रक्रिया का गहन परीक्षण किया गया है, और इसकी निगरानी विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई।

- भारत सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे नीरी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समय-समय पर अध्ययन किया।

-सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में निर्देश दिए थे कि केरल स्थित हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड लिमिटेड से कचरे का परिवहन कर पीथमपुर स्थित कामन हैजर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में निष्पादन किया जाए।

-अगस्त 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सफलतापूर्वक कचरे के निपटान का परीक्षण किया और रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि कचरे के निपटान से वातावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ।

पीएम मोदी का आज दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम गरीबों को मिलेंगे 1675 फ्लैट्स, 4500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, शुक्रवार (3 जनवरी) को दिल्ली में बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी गरीबों को 1675 फ्लैट्स की चाबी सौंपेंगे। इसके साथ ही 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के शहरी विकास और गरीबों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए, जानते हैं पीएम मोदी आज किन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे।

गरीबों को नए घर मिलने का इंतजार शुक्रवार दोपहर प्रधानमंत्री अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट्स दिल्ली विकास प्राधिकरण की इन-सीटू स्लम पुनर्विकास योजना के तहत बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स से हजारों गरीब परिवारों को घर का सपना पूरा होगा। इस योजना का मकसद झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन देना है। पीएम के इस कदम से जरूरतमंदों में उत्साह है।

द्वारका में CBSE बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी आज द्वारका में सीबीएसई की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह इमारत पर्यावरण अनुकूल है और हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त है। इसमें ऑफिस, ऑडिटोरियम, और डेटा सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

दो शहरी पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री दो प्रमुख शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय योजना शामिल हैं। सरोजिनी नगर की परियोजना में 28 टावर और 2500 से अधिक आवासीय इकाइयां हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा।

दिल्ली यूनिवर्सिटी को नई सौगात पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से तीन नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें सूरजमल विहार, द्वारका और नजफगढ़ के परिसर शामिल हैं। यह परियोजनाएं छात्रों को उच्च शिक्षा और बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विकास में यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है।

चुनावी सरगर्मी के बीच बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। ऐसे में पीएम मोदी का यह कार्यक्रम काफी अहम है। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने यहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब सभी दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी राजधानी में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस का देशव्यापी अभियानः जय बापू, जय भीम, जय संविधान के तहत देश भर में होंगी रैलियां,26 जनवरी को होगा समापन

कांग्रेस शुक्रवार(3 जनवरी) से देशभर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान का आगाज करेगी। कांग्रेस यह अभियान भारतीय संविधान और महात्मा गांधी की विचारधारा को बचाने के संकल्प के साथ शुरू कर रही है। इसका समापन गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में होगा। यह पहल कांग्रेस के हालिया बेलगावी अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई है। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के कारण अभियान की तारीख पहले टाल दी गई थी।

क्या है कांग्रेस के इस अभियान का मकसद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस अभियान के मकसद के बारे में बताते हुए कहा कि यह संविधान को बचाने और महात्मा गांधी की विरासत को बचाने की कोशिश है। देश

के हर ब्लॉक, जिले और राय में इस दौरान रैलियां होंगी। जरूरत पड़ने पर अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। कांग्रेस इस अभियान के जरिए लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेगी। इसके साथ ही भाजपा की नीतियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं को एकजुटत करने की कोशिश करेगी।

संविधान बचाओ पद यात्रा 26 जनवरी से 26 जनवरी से कांग्रेस एक साल लंबी संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करेगी। बेलगावी अधिवेशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस यात्रा का ऐलान किया था। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी को नई ऊर्जा दी थी, और यह नई यात्रा उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर कार्यकर्ताओं को इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में कहा है कि यह यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है।

भाजपा ने लगाया देश का गलत नक्शा दिखाने का आरोप भाजपा ने कांग्रेस पर अपने पोस्टरों में भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगाया है। भाजपा के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने होर्डिंग्स में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। रायसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने पोस्टर्स और होर्डिंग्स में कश्मीर और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। यह पार्टी की असली मंशा को उजागर करता है। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बताया है। यह नक्शा बेलगावी अधिवेशन से पहले लगाए गए पोस्टर में नजर आया था।

क्या है कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन का इतिहास कांग्रेस का बेलगावी अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में हुआ था। यह देश की आजादी की लड़ाई में एक अहम माइलस्टोन माना जाता है।

चीन में नए HMPV वायरस की दस्तकः ज्यादातर बच्चे आ रहे चपेट में, कोरोना जैसे हैं लक्षण... मचा हड़कंप

कोविड-19 के पांच साल बाद चीन में एक नए वायरस ने दस्तक दी है। पूरे देश में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के तेजी से फैलने की खबरें हैं। यह वायरस छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसके लक्षण कोविड-19 जैसे ही हैं। चीन में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें अस्पतालों और श्मशान घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित होने का दावा किया गया है। हालांकि, चीन सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

बच्चों पर ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस का असर इस नए वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो साल

से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक ऋ वायरस है। यह वायरस आम तौर पर सर्दी में फैलती है। इसकी चपेट में आने पर मरीजों में कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। बुखार, खांसी, नाक बंद होना और गले में घरघराहट होने लगी है। यह वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। डॉक्टरों के मुताबिक, अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए तो इस संक्रमण की वजह से ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। एक पोस्ट में दावा किया गया कि चीन में अस्पतालों और श्मशान घाटों पर भारी भीड़ है। बच्चों के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा पहले से बीमार लोगों को है। इस वायरस के चलते अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग शुरू चीन ने वायरस से निपटने के लिए निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर दी है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए सिस्टम के तहत अज्ञात संक्रमणों की पहचान की जाएगी। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सांस संबंधी समस्याओं के मामलों में भारी वृद्धि हुई।

संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत आज जय घोष से, मोहन भागवत होंगे शामिल

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के आयोजन की शुरुआत इंदौर से हो रही है। शुक्रवार को एक हजार से ज्यादा स्वयंसेवक वादन की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उद्बोधन देंगे। मालवा प्रांत से इस तरह का पहला आयोजन संघ कर रहा है। गुरुवार को इस आयोजन के लिए स्वयंसेवकों ने रिहर्सल की। दशहरा मैदान को आयोजन के लिए तैयार किया गया है। यहां एक डोम और मंच तैयार हो चुका है। कार्यक्रम में पंद्रह हजार लोग शामिल होंगे। इसमें संघ के स्वयंसेवकों के परिवारों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी, रंगकर्मी, व्यापारी व अन्य क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। शताब्दी वर्ष के अन्य आयोजन फरवरी से दूसरे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में भी होंगे। मावला प्रांत के स्वयंसेवको

का शिविर भी शहर में जारी है। इस शिविर का नाम स्वर शतकम् दिया गया है। राऊ के एक स्कूल में इस शिविर में मालवा प्रांत के 28 जिलों के 800 स्वयंसेवक शिविर में शामिल हुए हैं।

शिविर में शामिल वक्ता रघुवीर सिंह ने संघ के गठन से लेकर अब तक की यात्रा की जानकारी दी। इसके अलाव संघ की रीति-नीति व विचारधारा से भी अवगत कराया। शुक्रवार को जय घोष कार्यक्रम दोपहर तीन बजे शुरू होगा। पहले स्वयंसेवक वादन की प्रस्तुति देंगे। इसके बाद संघ प्रमुख अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के लिए मैदान के समीप ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

इस तरह होगा घोष वादन

घोष वादन में स्वयंसेवकों का बेहद खास और अनूठा अंदाज नजर आएगा। कार्यक्रम परिसर आनक, पणव, वंशी, शंख आदि विभिन्न वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से गूंजेगा। गणवेश पहने स्वयंसेवकों की वाद्ययंत्र पर तारतम्यता देखने को मिलेगी। आयोजन में शिक्षाविद्, उद्योगपति, चिकित्सक, प्रोफेशनल्स, खिलाड़ी, कलाकार, व्यवसायी भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

पूरा दशहरा मैदान सजाया गया

खास बात यह है कि संघ ने अब तक पांच सौ से ज्यादा समाजों से संपर्क किया है। सभी की भागीदारी रहेगी। पूरा दशहरा मैदान विशेष रूप से सजाया गया है। घोष वादन करने वाले एक हजार स्वयंसेवकों का खास प्रशिक्षण हुआ है। दरअसल,मालवा प्रांत संघ का गढ़ बन चुका है। संघ इस आयोजन को न केवल संख्या और व्यवस्था संचालन, बल्कि अनुशासन के लिहाज से भी आदर्श बनाने की तैयारी में जुटा है।

इंदौर में इस तरह का पहला कार्यक्रम

यह कार्यक्रम संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सरसंघचालक इस दौरान स्वयंसेवकों से समाज और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद करेंगे। यह इंदौर में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा, जो संघ की परंपराओं और विचारधारा को प्रदर्शित करेगा। कार्यक्रम के दौरान 28 जिलों के 1000 से अधिक स्वयंसेवक सरसंघचालक के समक्ष घोष वादन (संघ के परंपरागत वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन करेंगे।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मालवा और निमाड़ में तीन दिन तक रहेंगे। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। डॉ. भागवत के कार्यक्रम व संघ मुख्यालयों अर्चना और सुदर्शन पर भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार सरसंघचालक की मौजूदगी में देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार का वितरण समारोह में भी शामिल होंगे। राजेंद्रनगर स्थित नए लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में सैकड़ों वर्षों तक चले श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में वीरगति को प्राप्त हुए हुतात्माओं की स्मृति में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के वरिष्ठ नेता चंपत राय को इस वर्ष का देवी अहिल्याबाई होलकर ग्रहण करेंगे। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर से आठ बार सांसद रहीं सुमित्रा महाजन इस कार्यक्रम की सूत्रधार हैं। तीन दिवसीय प्रवास के दौरान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत निमाड़ क्षेत्र में ओंकारेश्वर और मंडलेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही कुछ और कार्यक्रम भी हैं, जो संघ स्तर पर होंगे।

स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इंदौर की तैयारियां तेज, एनजीओ का होगा सम्मान

लगी स्वच्छता की पाठशाला

निगम कमिश्नर ने पढ़ाया पाठ

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने अपनी योजनाओं और प्रयासों को नई दिशा दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और एनजीओ प्रतिनिधियों के लिए स्वच्छता जागरूकता और कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रविंद्र नाट्य गृह सभागृह में आयोजित हुआ, जहां आयुक्त शिवम वर्मा और अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता सर्वेक्षण की बारीकियों और उसकी आवश्यकताओं पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले और एनजीओ प्रतिनिधियों को बताया गया कि स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूकता कैसे लाई जाए और किस प्रकार शहर को स्वच्छता में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर लाने के लिए कार्य किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि सफाई से जुड़े हर पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वह कचरा प्रबंधन हो, सड़क और सार्वजनिक स्थानों की सफाई हो, या फिर नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना हो।

आठवीं बार भी नंबर वन आने की तैयारी

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को उनके सवालों के जवाब दिए गए और उनसे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर आयुक्त शिवम वर्मा ने घोषणा की कि स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्ड की एनजीओ टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा सभी प्रतिभागियों में उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने के उद्देश्य से की गई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने लगातार सात बार पहला स्थान प्राप्त किया है, और आठवीं बार भी यही उपलब्धि हासिल करने के लिए नगर निगम कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इस पाठशाला का आयोजन इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था, ताकि सभी कर्मचारी और एनजीओ प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें और मिलकर काम कर सकें। इसके साथ ही, कार्यक्रम ने नागरिकों को भी स्वच्छता में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। आयुक्त वर्मा ने कहा कि नगर निगम का मुख्य उद्देश्य शहर को न केवल स्वच्छता में नंबर एक बनाए रखना है, बल्कि स्वच्छता के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसमें सभी नागरिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें।

कार डस्टबिन वितरण कार्यक्रम शुरू

देश के सबसे स्वच्छ शहर बने रहने के लिए इंदौर में नई पहल की गई है। इंदौर नगर निगम ने चालकों को कार डस्टबिन मुहैया कराने का फैसला लिया। जिससे सड़कों पर थूकने और कचरा फेंकने जैसी स्थिति पर काबू पाया जा सके। इसके लिए साल 2025 के पहले दिन 1 जनवरी को पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने 500 कार चालकों को कार डस्टबिन वितरित किए। इंदौर को 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर की सूची में शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले शहर में स्वच्छता बरकरार रखने के लिए लगातार कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साल के पहले दिन कार डस्टबिन वितरण करने का निर्णय लिया गया। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शिवाजी प्रतिमा चौराहा से कार डस्टबिन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने चौराहे पर रुकने वाले कार चालकों को कार डस्टबिन देकर नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की।

स्वच्छता में लापरवाही पर हो रही कार्रवाई

निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। वहीं, निरीक्षण के दौरान सफाई कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें सफाई कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जोन 9 वार्ड 46 के दारोगा विजय नरवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार जोन 10 के सहायक सीएसआई संजय वेद का 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जोन 10 वार्ड 43 के दारोगा राहुल का भी 3 दिन का वेतन काटने के निर्देश हैं। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि सफाई व्यवस्था को सुधारने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

एमपीपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले नेताओं को भेजा जेल

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के दो सदस्यों को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। दोनों को बुधवार उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि वे बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों पर धारा 151 समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है। इससे पहले भी एमपीपीएससी न्याय यात्रा के दौरान उन पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री मोहन यादव की तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवा नेताओं को जेल भेजना क्या न्यायपूर्ण हैं जबकि जबकि 41 का नोटिस देकर मुचलके पर छोड़ने का नियम है

बुधवार को भंवरकुआं पुलिस ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के दो सदस्य राधे जाट और रंजीत को उनके घर से उठा लिया था। वे दोपहर 12 बजे डीडी पार्क में एक मीटिंग करने वाले थे। बताया जा रहा है कि कम पदों पर भर्ती के विरोध में वे डीडी पार्क पर अभ्यर्थियों के साथ बैठक करने वाले थे। इसके लिए राधे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो स्टेटस डाला था, जिसमें उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से आने की अपील की थी। बुधवार सुबह, जब अभ्यर्थी डीडी पार्क पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने राधे जाट और रंजीत किसानवंशी को उनके घर से उठा लिया। इसके बाद उनके साथियों ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, उमंग श्रृंगार सहित अन्य लोगों को टैग किया था।

उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर आयकर विभाग ने मारा छापा

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में भंवरकुआ स्थित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर छापामार कार्रवाई की गई। सुबह तीन इनोवा गाड़ियों में सवार आयकर विभाग के अधिकारी पुलिस टीम के साथ सेंटर पहुंचे। इस दौरान सुबह 8 बजे कोचिंग क्लासेस चल रही थीं। विभाग की टीम ने छात्रों को बाहर निकाला। इसके साथ ही सेंटर हेड और मौजूद स्टाफ के मोबाइल बंद करवा दिए। फिर दस्तावेजों और कंप्यूटर के डेटा की छानबीन शुरू की। उत्कर्ष कोचिंग के सेंटर्स पर देशभर में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सुबह करीब छह बजे जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज सहित अन्य केंद्रों पर अलग-अलग टीमें पहुंचीं। इन सभी सेंटरों पर अभी गहन छानबीन चल रही है। इसमें कई गड़बड़ियों की जानकारी सामने आने की सूचना है। इंदौर में भी इनकम टैक्स विभाग की टीम जुटी है। दिनभर में अलग-अलग बेचेस के स्टूडेंट्स जब सेंटर पहुंचे तो पता चला कि

अंदर छानबीन चल रही है। ऐसे ही कई फैकल्टीज को भी मौके पर पहुंचने पर इसकी जानकारी मिली। इसके चलते आज ऑन लाइन और ऑफ लाइन क्लासेस नहीं लगी। इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग की जॉइंट डायरेक्टर प्रेरणा चौधरी के निर्देशन में यह कार्रवाई हो रही है। जानकारी के मुताबिक, उत्कर्ष कोचिंग समूह के डायरेक्टर निर्मल गहलोत के राजस्थान स्थित उम्मेद हैरिटेज स्थित बंगले और संस्थान के बासनी मंडी के सामने स्थित मुख्यालय पर कार्रवाई चल रही है। यहां क्लासेस से बच्चों को बाहर निकालकर ऑफिस में रखे तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए गए। साथ ही अधिकारियों ने सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ के मोबाइल भी जब्त कर उन्हें वहीं पर बैठा दिया।

तीन महीने में पूरे होंगे दो अहम प्रोजेक्ट, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

इंदौर। मध्यप्रदेश में इंदौर रीजन में तेजी से औद्योगिक इकाईयां पैर पसार रही है। इससे न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, इसके साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यही कारण है कि मप्र औद्योगिक विकास निगम(एमपीआइडीसी) द्वारा इंदौर रीजन में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है। दो वर्ष पूर्व इंदौर में हुई सातवीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में तिलगारा(धार) और मोहना(धार) औद्योगिक पार्क प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था। 282 हेक्टेयर में विकसित हुए इस प्रोजेक्ट 3 हजार करोड़ रुपए के निवेश से 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। मोहना औद्योगिक पार्क फरवरी और तिलगारा औद्योगिक पार्क मार्च में पूरा हो जाएगा। धार जिले के आदिवासी अंचल में इस वर्ष इन दोनों प्रोजेक्ट के शुरू होते ही 10 हजार से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। जहां इंदौर से धार के बीच रेल मार्ग शुरू हो जाएगा। जिले के पेटलावद-बदनावर मार्ग से करीब चार किमी दूर तिलगारा औद्योगिक पार्क आकार ले चुका है। 79 करोड़ रूपये से यह प्रोजेक्ट मार्च माह में पूरा कर लिया जाएगा।

कुल मिलाकर आदिवासी अंचल धार में इस प्रोजेक्ट पूरा होते ही 5 हजार से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।

इस बहुउद्देशीय पार्क में अलग-अलग सेक्टर के उद्योग संचालित होंगे। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली विकसित की जाएगी। 1.6 हेक्टेयर में पार्किंग बनेगी।

रेत मंडी से हटाई पचास से ज्यादा अवैध दुकानें और ढाबे

वर्षों से था आईडीए की जमीन पर अवैध कब्जा

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रेत मंडी के आसपास से नगर निगम ने सुबह बड़ी अतिक्रमण विरोधी मुहिम को अंजाम दिया। यहां से 50 से ज्यादा दुकानें, ढाबे, अस्थाई शेड और पांच मकान तोड़े गए। वर्षों से इंदौर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जे थे। जमीन का मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट से फैसला प्राधिकरण के पक्ष में आया और नगर निगम ने जमीन अतिक्रमण मुक्त कर प्राधिकरण को सौंपी।गुरुवार सुबह छह जेसीबी, डेढ़ सौ से ज्याद श्रमिक और दो पोकलेन मशीनों के साथ नगर निगम की रिमूवल गैंग ने रेत मंडी पर धावा बोला। अतिक्रमणकारी मुहिम का विरोध भी कर रहे थे,लेकिन भारी पुलिस बल होने के कारण मुहिम नहीं रुक सकी। अफसरों ने कहा कि अतिक्रमण कोर्ट का फैसला आने के बाद हटाए जा रहे है।

रेत मंडी की यह जमीन प्राधिकरण की स्कीम 97 पार्ट-4 का हिस्सा है। स्कीम लागू होने से पहले यह कब्जे जमीन पर थे। अतिक्रमण होने के कारण प्राधिकरण जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहा था। इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में प्राधिकरण ने पक्ष रखा और कहा कि विधिवत रुप से जमीन अधिगृहित की गई है और जमीन मालिकों को तय मुआवजा भी दिया गया।

कोर्ट से फैसला प्राधिकरण के पक्ष में आने के बाद नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र भेजा गया था। इस आधार पर गुरुवार सुबह पचास से ज्यादा अतिक्रमण तोड़े गए। कुछ दुकानों में सामान भी भरा था। जिसे सुरक्षित हटाया गया। अब प्राधिकरण अतिक्रमण मुक्त करोड़ों की जमीन पर प्लॉट विकसित कर उसे बेचेगा।

छापे के 14 दिन बाद भी सौरभ शर्मा को खोज नहीं पाई पुलिस

विधिक सलाह ले रही लोकायुक्त पुलिस

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। लोकायुक्त छापे के 14 दिन बाद भी पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुंचा है। स्वजन मुताबिक वह दुबई में है। उसके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर भी जारी है, फिर भी उसके नहीं आने की स्थिति में आगे की कार्रवाई के संबंध में अब लोकायुक्त पुलिस विधिक सलाह ले रही है। इसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने से लेकर न्यायालयीन आदेश से संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की तैयारी है। अभी तक सिर्फ सौरभ की मां उमा शर्मा ने बयान दर्ज कराए हैं। छापे के दौरान सौरभ के स्वजन ने पुलिस को बताया था कि वह कार्रवाई के दो दिन पहले ही पत्नी दिव्या के साथ दुबई गया है। सूत्रों का कहना है कि उसका 21 दिसंबर को वापसी का टिकट था। इसके पहले ही 18 दिसंबर को सौरभ के आवास और कार्यालय में पुलिस ने छापा डाला था। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा सौरभ, उसके करीबी चेतन गौर, शरद जायसवाल, पत्नी दिव्या शर्मा और मां उमा शर्मा से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। आयकर विभाग की मांग पर एक सप्ताह पहले उसके विरुद्ध पिछले लुकआउट सर्कुलर भी जारी है।

इससे एयरपोर्ट या बंदरगाह पर पहुंचते ही उसे पकड़ा जा सकेगा। लोकायुक्त पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि संभवत: सौरभ भारत आ गया है। इसके बाद भी पुलिस पुख्ता तौर पर यह पता नहीं कर पाई है कि वह कहां है। सौरभ के करीबी शरद जायसवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अतिरिक्त समय मांगा है। चेतन गौर ने भी आयकर व ईडी में बयान दर्ज करा दिए हैं, पर लोकायुक्त पुलिस से दूरी बना रखी है। परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला यह शख्स भले ही जांच एजेंसियों की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन एक तरफ मध्यप्रदेश में इसके नाम पर जमकर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ हर दिन कुछ न कुछ नई जानकारी भी सामने आ रही है। अब सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति अस्थाई तौर पर दो साल के लिए हुई थी। वहीं उसका नियुक्ति पत्र वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र वायरल हुआ है, यह आदेश 29 अक्टूबर 2016 को जारी किया था, जहां परिवहन विभाग में सौरभ की दो साल की की परिवीक्षा अवधि के लिए अस्थाई नियुक्ति मिली थी, सौरभ की नियुक्ति का यह आदेश तत्कालीन परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जारी किया था। यह लेटर ग्वालियर से मिला है, बता दें कि सौरभ शर्मा मूल रूप से ग्वालियर का ही रहने वाला है, जहां उसके घर पर भी ईडी ने रेड मारी थी।

वहीं सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि अलग-अलग जांच एजेंसी इस मामले में लगी हैं, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। इसलिए किसी एक ही जांच एजेंसी को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं सौरभ शर्मा की जो लाल डायरी मिली है, उसका सच भी सबके सामने आना चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले की जांच ईडी को निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि यह बड़ा मुद्दा है।

तीन-तीन जांच एजेंसियां कर रही तलाश

लोकायुक्त ने सबसे पहले सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर पर छापा मारा था, जहां से उसे भारी मात्रा में अवैध संपत्ति मिली थी। इसके बाद उसके ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। इस बीच जानकारी आई कि सौरभ शर्मा अपनी पत्नी के साथ दुबई में मौजूद है। वहीं भोपाल में एक कार भी मिली थी, जो उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर थी, इस कार में 52 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। हालांकि सौरभ शर्मा के मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब तक वह गिरफ्त से दूर है। सौरभ शर्मा की तलाश आईटी-ईडी-लोकायुक्त तीन-तीन जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। फिलहाल सौरभ शर्मा के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है।

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके सहयोगियों के यहां ईडी के छापे में आखिर कितनी नकदी मिली, इसे लेकर संशय उत्पन्न हो गया है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और रोहित तिवारी के 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें चेतन सिंह के नाम पर 6 करोड़ की एफडी, सौरभ शर्मा के परिजनों के नाम पर बैंक खातों में 4 करोड़ रुपए और 23 करोड़ रुपए की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। हालांकि, मंगलवार को ईडी ने जानकारी दी कि छापेमारी में 6 करोड़ की एफडी, 4 करोड़ रुपए बैंक खातों में, 50 लाख की अचल संपत्ति और 23 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। फिर एक जनवरी को यह पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी गई। इसके बाद बुधवार को ईडी ने एक बार फिर से 23 करोड़ रुपए की संपत्ति का उल्लेख किया। ऐसे में ईडी 48 घंटे में तीसरी बार अपने आंकड़े बदले हैं। इससे पहले, 31 दिसंबर को ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी थी। पोस्ट में कहा गया था, ईडी भोपाल ने सौरभ शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ 27 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये की सावधि जमा, सौरभ शर्मा के परिवार के नाम पर 4 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस और 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति/संपत्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा ईडी ने बताया था कि इस दौरान 23 करोड़ रुपए कैश भी मिले हैं। 31 दिसंबर को ईडी ने 23 करोड़ की नकदी बरामद होना बताया था। फिर एक जनवरी को यह पोस्ट सोशल मीडिया से हटा दी गई। इसके बाद बुधवार को ईडी ने एक बार फिर से 23 करोड़ रुपए की संपत्ति का उल्लेख किया। इससे पहले 30 दिसंबर को एऊ ने ट्वीट कर सौरभ शर्मा के खिलाफ छापेमारी का खुलासा किया था। एऊ ने बताया था कि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह के नाम पर 6 करोड़ रुपए की एफडी, 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस और 23 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए।

संविदा नीति का लाभ नहीं मिलने से

नाराज संविदाकर्मियों का धरना जारी

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। संविदा नीति का लाभ नहीं मिलने से नाराज कुक्कुट विकास निगम के कर्मचारी नया साल शुरू होते ही धरने पर बैठ गए हैं। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारी पूरे परिवार समेत जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल है। संविदा कर्मचारी वेतन वृद्धि आदेश जारी करवाने की मांग को लेकर मुख्यालय के सामने परिवार सहित लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठे रहे।

दअरसल 19 जुलाई 2024 को प्रमुख सचिव गुलशन बावरा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई 2023 को जारी संविदा नीति का लाभ दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद वेतन वृद्धि आदेश आज तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे नाराज होकर संविदा कर्मचारी नए साल से धरने पर बैठ गए हैं। खास बात यह है कि यह संविदा कर्मचारी अपने छोटे बच्चों और पत्तियों के साथ धरने पर बैठे हैं। जबकि राजधानी में इस समय कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे प्रणय सक्सेना ने बताया कि वेतन वृद्धि आदेश न होने के कारण संविदा कर्मचारियों को 10,000 से 15,000 रुपए के

वेतन में गुजारा करना पड़ रहा है। वेतन वृद्धि आदेश की फाइल पिछले डेढ़ महीने से मंत्रालय (वल्लभ भवन) में अटकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बोर्ड की बैठक में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में निर्णय लिया जा चुका था, तो फाइल को मंत्रालय भेजने की जरूरत ही नहीं थी। धरना स्थल पर संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से तुरंत समाधान की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि उनकी वर्षों की मेहनत और सेवा को नजरअंदाज किया जा रहा है, और अब इस उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो गया है। संविदा कर्मियों ने इस आंदोलन को अपने अधिकारों की लड़ाई करार देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक यह धरना जारी रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, उनके परिवार और अन्य समर्थन करने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। ठंड के बावजूद उनकी हिम्मत और संघर्ष भावना देखते ही बनती है।

अब एक क्लिक पर मिल जाएगा

नया बिजली कनेक्शन

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। 2025 में नागरिकों को नई सुविधा मिलने जा रही है। इसके बाद से उपभोक्ताओं को बिजली का बिजल जमा करने के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। बिल जमा करने की प्रक्रिया को अत्यधिक आसान बनाने की दिशा में कंपनी यह कार्य करने वाली है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह यानि इसी महीने से एमपी ऑनलाइन पर भी बिल जमा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर कोई नागरिक नए कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उसी के माध्यम से आवेदन मिल जाएगा। आपको बता दें कि बिजली कंपनी द्वारा भोपाल सहित अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर चुकी है। इसी के चलते यह नई सुविधा भी शुरू की जा रही है।

गौरतलब है कि मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आनलाइन बिजली बिल जमा करने की सुविधा शुरू करने के लिए एमपी ऑनलाइन से अनुबंध किया है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल, निदेशक वाणिज्य सुधीर कुमार श्रीवास्तव और एमपी ऑनलाइन के चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी प्रशांत राठी मौजूद थे।

बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को सौगात देगी। इससे प्रदेश के आम लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से फायदा होगा। उनका समय भी बचेगा साथ ही भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी।

भेल में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। ठेका श्रमिकों के लिए नया पुनरीक्षित वेतन लागू करने और एरियर सहित भुगतान कराने की मांग को लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने गुरुवार को भेल में विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिक और कर्मचारियों ने कारखाने के गेट-5 पर द्वार सभा की और कारखाना प्रबंधन को श्रमिकों की मांगें बताईं। वहीं श्रमिकों के न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुहार लगाई। सीटू प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान एवं सीटू भेल के महामंत्री दीपक गुप्ता ने चेतावनी दी कि पुनरीक्षित वेतन के आदेश जल्द जारी नहीं हुए तो सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। गुप्ता ने बताया कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) प्रबंधन से स्थाई भर्ती, ईएल नगदीकरण, नई इंसेंटिव स्कीम, नाइट एलाउंस रिवीजन, लैपटॉप प्रतिपूर्ति प्रारंभ करने सहित अन्य मांगें हैं, जो लंबे समय से लंबित हैं। भेल प्रबंधन कर्मचारियों की इन ज्वलंत मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने ठेका श्रमिकों के पुनरीक्षित वेतन पर लगी रोक भी हटा दी है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक ठेका श्रमिकों का बढ़ा हुआ वेतन लागू नहीं किया है। ये हाईकोर्ट के आदेश की अव्हेलना है। इन्हीं ज्वलंत मांगों को लेकर भेल कर्मचारी एवं ठेका श्रमिक भेल प्रबंधन और राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं।

नए साल के पहले दिन 2 लाख लोग उज्जैन, 1 लाख ओंकारेश्वर पहुंचे

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। मध्यप्रदेश के नागरिकों ने अंग्रेजी नववर्ष का स्वागत धार्मिक स्थलों में जाकर किया हैं। उज्जैन महाकालेश्वर, ओरछा, मैहर, बगलामुखी, ओंकारेश्वर, खजराना-चिंतामन गणेश, भोजपुर जैसे कई मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल ज्योतिर्लिंग में तो करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। 1 जनवरी के तड़के 3 बजे से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पचमढ़ी में नये वर्ष का आगाज किया। वे मंगलवार को ही हिल स्टेशन पहुंच गए थे। इसे दौरान उन्होंने धूपगढ़ में भी समय बिताया, इसे लेकर उनका वीडियो भी सामने आया है। खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किये। दतिया के पीतांबरा पीठ में माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भोपाल के नजदीक

स्थित रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर में में करीब 50 हजार श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा के दर्शन के लिए करीब एक लाख लोग पहुंचे। मैहर जिले के मां शारदा के दरबार में नए साल के पहले दिन देवी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर वन विहार नेशनल पार्क, अरेरा हिल्स पहाड़ी स्थित शौर्य स्मारक, सैर सपाटा, म्यूजियम, बोट क्लब, और लेक व्यू में लोग परिवार समेत पहुंचे।

मप्र में बनी पहली फायर फाइटिंग बोट, पानी के बीच से बुझा सकती है आग

सिटी चीफ इंदौर।

भोपाल। भोपाल में देश की पहली फायर फाइटिंग बोट तैयार हो गई है। यह बोट प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ में इस्तेमाल होगी। इस बोट से घाटों पर आग लगने की स्थिति में तुरंत मदद मिलेगी। इस बोट को खासतौर पर कुंभ मेले की भीड़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस और मध्य प्रदेश एसडीआरएफ की टीम मिलकर इसकी टेस्टिंग कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखी बोट का निर्माण हुआ है। यह देश की पहली फायर फाइटिंग बोट है। इस बोट को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में तैनात किया जाएगा। इस बोट की खासियत यह है कि यह पानी में रहते हुए आग बुझाने में मदद करेगी। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में आग लगने की स्थिति में भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस बोट को बनाया गया है। इस बोट को अलग-अलग घाटों पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।

अलग-अलग घाटों पर होगी तैनात

इस बोट के निमार्ता राजेंद्र गिरी ने बताया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़भाड़ को देखते हुए बोट का निर्माण किया गया है। भीड़ के चलते कई इलाकों में आपात स्थितियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिए फायर फाइटिंग बोट को अलग-अलग घाटों पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि यह बोट आग लगने की किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाएगी। इससे आग बुझाने के साथ-साथ फंसे हुए लोगों को बचाने में भी मदद मिलेगी।

गंगा नदी से पानी खींचकर बुझाएगी आग

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव भी इस बोट की टेस्टिंग के लिए भोपाल आए हैं। उन्होंने बताया कि इस बोट की टेक्निकली जांच कर प्रयागराज महाकुंभ-2025 में तैनाती की जाएगी। अभी दो-तीन दिक्कतें देखने को मिली है, जिन्हें सुलझाकर जल्द ही इसको प्रयागराज के लिए भेजा जाएगा। यहां से छह बोट प्रयागराज के लिए रवाना होंगी, जो किसी भी आपात स्थिति में गंगा नदी से पानी खींचकर आग बुझाने में सहयोग करेगी।

आग बुझाने के साथ लोगों की मदद भी करेगी

महाकुंभ में ऐसी छह बोट तैनात की जाएंगी। यह बोट श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आग जैसी आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। यह बोट न सिर्फ आग बुझाएगी बल्कि लोगों को बचाने में भी मददगार साबित होगी। इस तरह की बोट पहले कभी नहीं बनाई गई थी, इसलिए यह अपने आप में एक अनोखा प्रयास है।

सम्पादकीय

मणिपुर में भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा...

मणिपुर हिंसा को लेकर वहां के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य की जनता से माफी मांगी है, लेकिन यहां भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता के साथ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। मणिपुर जलता रहा और हल ढूंढने में न तो केंद्र ने और न ही राज्य की सरकार ने कभी राजनीतिक इच्छाशक्ति का इजहार किया। वहां हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की ताजा रपट से यह स्पष्ट है। वर्ष 2023 में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई हिंसा में से 77 फीसद घटनाएं मणिपुर में हुईं।

मणिपुर हिंसा को लेकर वहां के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य की जनता से माफी मांगी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2024 बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं बहुत अफसोस महसूस कर रहा हूं और राज्य के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान बहुत से लोग अपने प्रियजनों को खो बैठे, कई लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए। मुझे सच में खेद है। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी समुदायों से अपील की कि जो कुछ भी हुआ, वह हो चुका है। अब हमें पिछली गलतियों को भूलना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर की दिशा में आगे बढ़ना है और हम सभी को मिलकर एक साथ रहना है। इस बयान के दूसरे दिन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने जातीय संघर्ष के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। एन.बीरेन सिंह ने कहा कि उनका बयान उन नागरिकों के लिए दुख व्यक्त करने का एक ईमानदार कार्य था, जो विस्थापित और बेघर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर में कांग्रेस द्वारा पूर्व में किए गए पापों के कारण अशांति है. उन्होंने सस्पेंशन ऑफ समझौते पर भी सवाल उठाए हैं। कुछ भी हो जातीय हिंसा से त्रस्त घायल मणिपुर को समाधान का इंतजार है। यहां भावनात्मक बातों से काम नहीं चलेगा। संवेदनशीलता के साथ गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। मणिपुर जलता रहा और हल ढूंढने में न तो केंद्र ने और न ही राज्य की सरकार ने कभी राजनीतिक इच्छाशक्ति का इजहार किया। वहां हालात बेहद खराब रहे हैं। गृह मंत्रालय की ताजा रपट से यह स्पष्ट है। वर्ष 2023 में समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई हिंसा में से 77 फीसद घटनाएं मणिपुर में हुईं। वहां बहुसंख्यक मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में सैकड़ों नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान गई। महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह के वीडियो आए, वे किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा थे। वहां तीन मई, 2023 को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा भड़क उठी। हिंसा का दौर अभी भी जारी है। जबकि सरकार का दावा है कि बीते कुछ महीनों से स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अब जाकर राज्य में हुए जातीय संघर्ष के लिए माफी मांगी है और सभी समुदायों से पिछली गलतियों को भूलने तथा एक साथ रहने की अपील की है। प्रदेश में हुए जातीय संघर्ष में 250 से अधिक लोगों की जान चली गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। यह याद रखा जाएगा कि जब मणिपुर में हिंसा की कई घटनाएं राष्ट्रीय सुर्खियां बनीं, तब बीरेन सिंह या केंद्र की सरकार के स्तर पर चुप्पी रही। विपक्षी कांग्रेस तो अब तक यह सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर चुप क्यों हैं? वे दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने से परहेज क्यों करते हैं। दरअसल, वहां की स्थिति से निपटने में अक्षमता के बावजूद मुख्यमंत्री बीरेन सिंह सत्ता में बने रहे, उनकी पार्टी उनके साथ हठपूर्वक खड़ी रही। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई। अब जबकि, वहां का समाज बुरी तरह से बंट गया और समरसता दूर की कौड़ी हो गई है, बीरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने वहां के लोगों को भरोसे में लिए बगैर दो फैसले लिए, जो विवादित रहे, भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना और मुक्त आवागमन व्यवस्था खत्म करना। इन फैसलों का मणिपुर में कई आदिवासी संगठनों ने विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने वहां की स्थिति पर स्वत- संज्ञान लेते हुए निगरानी और जांच समितियां गठित कर दी थीं। उसमें बाहरी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। उम्मीद बनी थी कि हिंसा की हकीकत जल्द ही सामने आएगी। मणिपुर कोई इतना बड़ा और जटिल राज्य नहीं है कि वहां की स्थितियों से निपटना मुश्किल हो। विवाद भी एक भ्रम की वजह से पैदा हुआ था। अगर सरकार संजीदा होती, तो दोनों समुदाय के लोगों को आमने-सामने बिठा कर मसले का हल निकाल चुकी होती।

2025 का साल... संघ के 100 साल का सपना साकार

साल 2024 अलविदा हो चुका है और हम साल 2025 में प्रवेश कर गए हैं। राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के लिहाज से 2025 दुनिया के सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 2025 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना के सौ साल पूरे हो जाएंगे। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ आरएसएस मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। संघ आज जितना मजबूत और पावरफुल नजर आ रहा है, उसके लिए कई उतार-चढ़ाव भरे दौर से उसे गुजरना पड़ा है।

साल 2024 अलविदा हो चुका है और हम साल 2025 में प्रवेश कर गए हैं। राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य के लिहाज से 2025 दुनिया के सबसे बड़े गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काफी अहम माना जा रहा है। 2025 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना के सौ साल पूरे हो जाएंगे। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ आरएसएस मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। संघ आज जितना मजबूत और पावरफुल नजर आ रहा है, उसके लिए कई उतार-चढ़ाव भरे दौर से उसे गुजरना पड़ा है। इस तरह 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित है।

संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में लक्ष्य रखा है कि तब तक देशभर में अपनी शाखाओं की संख्या बढ़ाकर एक लाख करनी है। सौ साल के सफर को पूरा करने पर संघ तब कई बड़े आयोजन भी करेगा और जिसका राजनीति परिदृश्य में भी असर दिखेगा। संघ ने 2025 के लिए जो अपना एजेंडा बनाया है, उसमें अपनी शाखा को शहर और कस्बों में नहीं बल्कि गांव तक अपनी जड़ें जमाने का है। इतना ही नहीं संघ का सामाजिक समरसता का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके जरिये जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करने की है।

विपक्ष एक तरफ जातिगत जनगणना, संविधान और आरक्षण के मुद्दे को धार देने के साथ-साथ डॉ. भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर सियासी एजेंडा सेट करने में जुटा हुआ है, इतना ही नहीं कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है। ऐसे में संघ के लिए दलित और आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने के साथ गांव-गांव में पैर पसारने की चुनौती है। हालांकि, बीजेपी पहले की तरह ही विपक्षी दलों के इस सियासी एजेंडे को विभाजनकारी बताते हुए अपनी मुहिम जारी रख सकता है। सामाजिक समरसता अभियान के जरिये ही आरएसएस ने कई चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनाने का काम जमीनी स्तर पर बखूबी किया है। संघ पिछले कई वर्षों से गांव में एक श्मशान, एक मंदिर और एक जल स्रोत के विचार पर काम कर रहा हैं।

आरएसएस इस एजेंडे के जरिये चाहता है कि मंदिर को लेकर कोई भेदभाव न हो, जल स्रोत में कोई छुआछूत न हो और न ही जातियों के अलग-अलग श्मशान हों। इस तरह जातियों के भीतर श्रेष्ठता का भाव इन तीनों ही स्थानों पर कहीं न दिखाई दे। इसे लेकर संघ काफी समय से कार्यक्रम करता रहा, लेकिन अब इसका असर दिखाई भी देने लगा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते रहे हैं कि कि भारत के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में एक संघ की शाखा होनी चाहिए, क्योंकि पूरे समाज ने उन्हें उनके लिए काम करने का अवसर दिया है। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों को आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करना चाहिए।

दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। इस लिहाज से 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अण्णा साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे सब कुछ समय के साथ धीरे-धीरे तय होता गया।

हालांकि, उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहां तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ और हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। डॉ. हेडगेवार ने संघ स्थापना के बाद पूरी शक्ति लगा थी। इसलिए पहले 50 साल संघ ने केवल संगठन पर काम किया। इस पहले दौर में संघ ने कई संस्थाएं बनायीं, जिसमें राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिन्दू परिषद, भारतीय जनसंघ/भारतीय जनता पार्टी और सरस्वती शिशु मंदिर/विद्या भारती जैसे संगठन शामिल हैं।

संघ ने अपने सौ साल के लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित की जबकि तीन बार उस पर प्रतिबंध भी लगा। संघ पर 1932 और 1940 में शासन ने आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वे ज्यादा नहीं चल सके। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया, संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया। लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। तब शासन, प्रशासन और जनता संघ के विरोध में थी। इसके बाद दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार छह महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद सरकार ने फिर प्रतिबंध लगाया, जिसे न्यायालय ने ही खारिज कर दिया।

संघ के शाखा के साथ ही समविचारी संगठनों का विस्तार और प्रभाव बढ़ने लगा। इसलिए जब संघ पर प्रतिबंध लगाया, तो बहुसंख्यक समाज आरएसएस के साथ खड़ा रहा है। चाहे आपातकाल की बात हो या फिर बाबरी विध्वंस के दौरान। इसीलिए चुनाव में संघ के समर्थन वाली चाहे जनता पार्टी रही हो या फिर बीजेपी। उसे जीत मिली। समाज में बढ़ती स्वीकार्यता का लाभ उठाकर संघ ने अपने संगठन को विस्तार दिया और स्वयंसेवकों ने अनेक नयी संस्थाएं बनाने का काम किया।

संघ ने अनुभव किया कि हिंदू समाज में गरीबी है, जिसकी पहली जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। इसके अलावा सामाजिक और जाति भेदभाव भी धर्मांतरण का एक बड़ा कारण रहा, जिसके चलते संघ ने सामाजिक समरसता और वनवासी कल्याण के कार्यक्रम शुरू किए। 1989 में डॉ. हेडगेवार की जन्मशती पर सेवा निधि एकत्र कर हजारों पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाये गये, जो निर्धन बस्तियों को सेवा बस्ती कहकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हजारों छोटे प्रकल्प शुरू किए। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए संघ ने विश्व हिंदू परिषद की गठन किया था, जिसने राम मंदिर, गौ-रक्षा जैसे अभियान और आंदोलन चलाए।

आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवकों ने ही पहले जनसंघ के रूप में राजनीतिक दल का गठन किया और उसके बाद बीजेपी के रूप में राजनीतिक पार्टी बनाई। देश की सत्ता पर 2014 से बीजेपी काबिज है। इतना ही नहीं देश के 13 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पर सरकार चल रही है तो कई राज्यों में सत्ता की भागीदार है। बीजेपी के सत्ता में होने के चलते संघ अपने कोर एजेंडे को भी अमलीजामा पहनाने में कामयाब रहा है।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई है। एक देश, एक विधान का सपना भी संघ का साकार हो चुका है। संघ का कोर एजेंडा समान नागरिक संहिता का है, जिसे अमलीजामा पहनाने का काम भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है।

उत्तराखंड के जरिए यूसीसी का सियासी प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करेंगे। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की मिसाल भी दी है।

संघ कभी संगठन के लिए संगठन की बात करता, पर 50 साल संगठन और 50 साल विस्तार के बाद अब संघ समाज परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जहां संघ का काम पुराना है, वहां परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग, सामाजिक समरसता, एक मंदिर, एक श्मशान, एक जल स्रोत, नागरिक कानूनों के पालन है। संघ अपना प्रयास इस दिशा में करेगा। संघ कार्य की विकास यात्रा का यह चौथा पड़ाव है। संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार ने 1940 के शिक्षा वर्ग में कहा था कि संघ कार्य को शाखा तक ही सीमित नहीं रखना है, उसे समाज में जाकर करना है।

धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सौहार्द के लिए गो-वध निषिद्ध होना चाहिए!

हमारा देश भारत अनेकता में एकता का सम्मान करने वाला एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां कई धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलजुलकर निवास करते हैं। यहां की आबादी में हिंदू लगभग 80 प्रतिशत हैं, जबकि मुस्लिम लगभग 15 प्रतिशत हैं। ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोग गाय को पवित्र पशु के रूप में मानते हैं और उसे अति सम्मान की नजर से देखते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करना, सद्भाव से रहना और ऐसे किसी भी काम से बचना है, जो दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकता है या समाज में अनेक समस्याएं पैदा कर सकता है।

इस्लाम में, हमारा धर्म हमें दूसरों के साथ शांति से रहना और उनकी परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करना सिखाता है। कुरान हमें ऐसे काम करने से बचने के लिए कहता है, जो दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर इससे बहस या हिंसा हो। जब हम समझते हैं कि भारत में अधिकतर लोग गाय को पवित्र मानते हैं, तो एक सच्चे मुसलमान के तौर पर यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। यह प्यार और दोस्ती को सम्मान देकर सौहार्द और आपसी प्रेम को बढ़ानेवाले तरीके से जीने के बारे में है।

भारत में सामाजिक तनाव और हिंसा का एक बड़ा कारण गो-हत्या रहा है। हाल के वर्षों में, भीड़ द्वारा हमले और लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं, जहां गो-हत्या या गोमांस खाने के आरोप में कई लोगों को पीटा गया या यहां तक कि मार दिया गया। इनमें से कई हमले गलतफहमी या अफवाहों के कारण हुए। ऐसी घटनाएं समुदायों के बीच विभाजन पैदा करती हैं, जिससे लोगों का एक-दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है।

भारत में गो-हत्या के इतने बड़े मुद्दे बनने का एक कारण यह है कि गाय हिंदू संस्कृति के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। गाय को अकसर गौ माता कहा जाता है, जिसका अर्थ है गाय माता। हिंदुओं का मानना है कि गाय दयालुता,देखभाल और निस्वार्थ भाव से देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह मनुष्योंको दूध प्रदान करती है। गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में, गायों को परिवार का सदस्य भी माना जाता है और कई परिवार डेयरी फार्मिंग के जरिए अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं।

भारत दुनिया का एक बड़ा दूध उत्पादक है, जो वैश्विक डेयरी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लाखों किसान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी आय के लिए गायों पर निर्भर हैं। भारतीय डेयरी उद्योग देश की कृषि की आधारशिला है, जिसका दूध उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया। यह पिछले वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि को दशार्ता है, जो इस क्षेत्र के विकास और महत्व को रेखांकित करता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जहां प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। इसलिए, जब गायों का वध किया जाता है, तो यह इस व्यवस्था को बाधित करता है और गांवों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। गायों की रक्षा करना किसानों की आजीविका का समर्थन करने और देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में है। इस्लाम में, जानवरों की बलि देना धार्मिक प्रथाओं का एक हिस्सा है, खासकर ईद-उल-अजहा के दौरान। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में विशेष रूपसे गायों की बलि की आवश्यकता नहीं है। अन्य जानवर, जैसे बकरी, भेड़ या भैंस, की भी बलि दी जा सकती है। भारत जैसे देश में, जहां गो-हत्या इतना तनाव पैदा करती है, विकल्प चुनना दूसरों को चोट पहुंचाने से बचने का एक सरल तरीका है और साथ ही अपने धार्मिक कर्तव्यों को भी पूरा करना है।

2017 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू की। यह कदम उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से प्रमुख था और इसका उद्देश्य मौजूदा कानूनों को लागू करना और मांस उद्योग को विनियमित करना था। इस पहल के तहत कई अपंजीकृत और अनियमित बूचड़खानों को बंद कर दिया गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक रहा है, जहां पिछले कुछ वर्षों में दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है।

2023 में, देश का दूध उत्पादन 230 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो स्थिर वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि दूध देने वाली गायों की बढ़ती आबादी और बेहतर डेयरी फार्मिंग तकनीकों के कारण है। दूध देने वाली गायों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें संकर या विदेशी गायों की संख्या 25 प्रतिशत है, जबकि कुछ साल पहले यह 15 प्रतिशत थी। गायों की रक्षा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करती है, जो लाखों ग्रामीण किसानों का समर्थन करती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है।

2016 से 2020 तक, गोहत्या या गोमांस खाने के आरोपों से संबंधित भीड़ की हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये दुखद घटनाएं अकसर गलतफहमियों, झूठी अफवाहों या सोशल मीडिया पर गलत सूचना के कारण होती हैं। इस तरह की हिंसा ने समुदायों के बीच विभाजन पैदा किया है और भारत में शांति और एकता बनाए रखने के लिए इन मुद्दों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित किया है। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करके और हिंसा को बढ़ावा देनेवाली गलत सूचनाओं के प्रसार को रोककर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है।

हमारा इतिहास बताता है कि हिंदू और मुसलमान सदियों से शांतिपूर्वक साथ रहते आए हैं। मुगल काल में अकबर और जहांगीर जैसे शासकों ने हिंदू प्रजा की मान्यताओं का सम्मान करने के लिए गोहत्या से परहेज किया। इन भावनाओं का सम्मान करने के उनके फैसले ने साम्राज्य में शांति और एकता बनाए रखने में मदद की। अगर वे सैकड़ों साल पहले इस स्तर की समझदारी और उदारता का दिखा सकते थे, तो हम आज की आधुनिक दुनिया में भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं।

गोहत्या से जुड़ी हिंसा अकसर समझ और संवाद की कमी के कारण होती है। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि बहुसंख्यकों की मान्यताओं का सम्मान करने का मतलब अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब बस एक संतुलन बनाना है, जो सुनिश्चित करता है कि हर कोई शांति से रह सके। गो-हत्या से बचना सम्मान दिखाने और अनावश्यक संघर्षों को रोकने का एक तरीका है।

हाल के वर्षों में, सोशल मीडिया ने गो-हत्या के बारे में गलत जानकारी फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। गायों को नुकसान पहुंचाने का दावा करने वाले वीडियो और संदेश अकसर वायरल हो जाते हैं, भले ही वे दावे सच न हों। इससे लोगों में गुस्सा पैदा होता है, जिससे भीड़ हिंसा करती है। हर किसी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जानकारी को शेयर करने से पहले उसे सत्यापित करें और ऐसी अफवाहें फैलाने से बचें जो परेशानी पैदा कर सकती हैं।

मुसलमान होने के नाते, हमारे पास अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने की शक्ति है। गायों का वध न करने का निर्णय लेकर और खुले तौर पर शांति और सम्मान को बढ़ावा देकर, हम दिखा सकते हैं कि हम बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को महत्व देते हैं। यह छोटा सा कदम विश्वास बनाने और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अक्सर मौजूद अविश्वास को कम करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। इस मुद्दे को हल करने में शिक्षा एक और महत्वपूर्ण कारक है।

स्कूलों और कॉलेजों को बच्चों को दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करने और शांति से एक साथ रहने के महत्व के बारे में सिखाया जाना चाहिए। जब युवा लोग हिंदुओं के लिए गायों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में जानेंगे, तो वे यह समझने में बेहतर ढंग से सक्षम होंगे कि गोहत्या से बचना क्यों महत्वपूर्ण है।

धार्मिक नेता भी सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अपने प्रभाव का उपयोग अपने समुदायों को दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। शांति और समझ का संदेश देकर, वे तनाव को कम करने और हिंसा को रोकने में मदद कर सकते हैं।

इस मुद्दे को संभालने में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। बूचड़खानों में नियमों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। साथ ही, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समुदाय लक्षित या भेदभाव महसूस न करें। एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली लोगों के बीच विश्वास बनाने में मदद करेगी। मीडिया आउटलेट्स को भी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना चाहिए। गोहत्या या भीड़ हिंसा से जुड़ी घटनाओं को सनसनीखेज बनाने के बजाय, उन्हें एकता और सहयोग की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कलेक्टर ने किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण

कर्मचारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

गणेश वैष्णव । सिटी चिफ
नारायणपुर, कलेक्टर बिपिन मांझी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयरहाउस मासिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए वोटिंग मशीन की रखरखाव संबंधी जानकारी ली तथा उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग, निर्वाचन सुपरवाइजर जिवेन्द्र ठाकुर, सहायक प्रोग्रामर हेमंत देवांगन उपस्थित थे।

बस्तर क्षेत्र के चुनौती भरे माहौल में पत्रकारिता करने के साहस को नमन - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर पत्रकार संघ के पदाधिकारियों को दिलवाई शपथ

गणेश वैष्णव । सिटी चिफ
जगदलपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर जैसे क्षेत्र में पत्रकारिता करना एक बड़ी चुनौती है, क्षेत्र की समस्याओं, आम जनता की आवाज बनकर शासन-प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने की साहस को नमन है। बस्तर के विकास हेतु पत्रकारों के प्रयास सतत जारी रहे, आप लोंगों के प्रयास से प्रदेश की नकारात्मक छवि को दूर करने में सहायक हुए। छवि में सुधार होने के साथ ही इस बार तीस लाख से अधिक पर्यटक प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पहुँचे है। उन्होंने बस्तर पत्रकार संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी। कार्यक्रम में

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर पत्रकार संघ के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पदीय दायित्व के प्रति निष्ठा, समर्पण की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के उच्च आदर्शों का पालन कर सरकार के अच्छे काम की जानकारी जनता को दें तथा कमियों को भी बताएं। वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने संघ के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि बस्तर की समस्याओं को आवाज बनने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। विधायक जगदलपुर श्री किरण देव ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने में बस्तर के पत्रकारों महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यक्रम में बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री मनीष गुप्ता ने स्वागत उद्बोधन दिए। इस अवसर पर खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा, चित्रकोट, दंतेवाड़ा और केशकाल विधायक सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

धीरे-धीरे आशा बंधी और बन गया पक्का मकान

सुबरी बाई ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जताया आभार

गणेश वैष्णव । सिटी चिफ
जगदलपुर, कभी खुद का पक्का मकान बनाना सपने से कम नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूची में नाम आने से धीरे-धीरे आशा बंधी और मेरा पक्का मकान बन गया। ये कहना है, दूरस्थ वंनाचल क्षेत्र लोहण्डीगुड़ा में रहने वाली सुबरी बाई का, जिसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जगदलपुर स्थित अजजा पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन में उसे नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत् उसके घर की चाबी सौंपी। सुबरी बाई ने बताया कि लंबे समय तक कच्चे घर में रहने के कारण हर बारिश के मौसम में छत टपकने और पानी घुसने की चिंता बनी रहती थी। साथ ही बंदरों द्वारा भी उनके कच्चे मकान में खूब उत्पात मचाया जाता था। कच्चा आवास होने के कारण जहरीले जीव जंतुओं के घुसने का

भी खतरा बना रहता था। सुबरी बाई ने प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उन्हें अपने घर की सुरक्षा और आराम का भरोसा है। प्रशासन ने उनकी मदद की, जिसके कारण उनका घर बन सकेगा। बारिश के दौरान जो समस्याएं पहले उन्हें हर साल झेलनी पड़ती थी, अब उनसे मुक्ति मिलेगी। इस पक्के आवास के मिलने से उनका जीवन सरल और सुरक्षित रहेगा और उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आवास योजना हम जैसे गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

सहारनपुर के प्रसिद्ध वुड कार्विंग कारोबारियों और निर्यातकों को नए साल में व्यवसाय बढ़ने की उम्मीद - निर्यातक मो. असलम सैफी

सुरेंद्र सिंघल/गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, विश्वभर में लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पादों की मांग बढ़ रही है। लेकिन अनेकानेक कारणों से भारत पिछड़ रहा है। जिससे इस विश्व प्रसिद्ध कारोबार के केंद्र सहारनपुर के उद्यमी और निर्यातक बेहद मायूस हैं। जबकि यहां के निर्यातकों को उम्मीद थी कि भारत विश्व में अपने ज्यादा से ज्यादा अपने उत्पादों को निर्यात कर सकें। इस संबंध में सहारनपुर के कारोबारियों, उद्यमियों और निर्यातकों से आज नए साल के पहले दिन वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंघल और गौरव सिंघल द्वारा बातचीत की गई तो सहारनपुर के एक बड़े निर्यातक एवं प्रमुख उद्यमी मोहम्मद असलम सैफी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों इस उद्योग और कारोबार की ओर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो आज से शुरू हो नए साल में सहारनपुर दुनिया में अपना पुराना मुकाम

हासिल कर सकता है। मोहम्मद असलम सैफी ने कहा कि अकेले सहारनपुर शहर में ही लाखों लोगों का यह व्यवसाय जीवन यापन का मुख्य जरिया है। उन्होंने कहा कि भारत के उत्पाद दुनिया में गुणवत्ता और कलात्मक नजरिए से बहुत ही पसंद किया जाता है। लेकिन भारत को सबसे बड़ी टक्कर चीन से मिल रही है। चीन की सरकार कुशल कारीगरों, उद्यमियों और निर्यातकों को बहुत प्रोत्साहन देती है। जबकि भारत में उद्यमियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। बहुत से उद्यमियों की सरकार से यह भी शिकायत है कि सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि एवं अन्य सुविधाएं नगण्य मात्र है। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारी सीजनिंग प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट थे उनमें उद्यमियों को लकड़ी सुखाने के लिए 75 फीसद सब्सिड़ी मिलती थी जिसे बंद कर दिया गया है। इन दोनों कामों को निजी हाथों में सौंप दिया है जो अब उद्यमियों से पूरा शुल्क लेते हैं। पहले निर्यातकों को निर्यात पर दो से ढाई फीसद सब्सिड़ी मिलती थी अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया हैं जबकि लकड़ी और कारीगरों की मजदूरी में करीब-करीब दोगुना इजाफा हो गया है यानि कि मजदूरी भी बढ़ी और लकड़ी के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। मोहम्मद असलम सैफी ने बताया कि पिछले साल सहारनपुर का कुल सालाना निर्यात करीब 250 करोड़ रहा जबकि पूर्व के वर्षों में यह निर्यात 600 करोड़ रूपए सालाना तक रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि वे सहारनपुर के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिजली के दामों में कमी करे। उन्होंने कहा कि पहले विद्युत दर पांच रूपए प्रति यूनिट थी अब सात रूपए प्रति यूनिट से भी ऊपर है। सरकारी प्रोत्साहन ना मिलने से यहां के सैकड़ों साल पुराने कारोबार की कमर टूटी है। डीजल की दरों में भी बढ़ोतरी की मार इस उद्योग पर पड़ी है। सहारनपुर का यह उद्योग केंद्र सरकार के थोड़े से प्रोत्साहन मिलने पर भी भारत के लिए अरबों की विदेशी मुद्रा ला सकता है। इससे कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार मिलेगा और छोटी-छोटी इकाइयां आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कई उद्यमियों ने यह शिकायत की कि जिले के पिलखनी में कलस्टर के जरिए बनाए गए औद्योगिक स्थान में लघु इकाइयों को जगह नहीं दी गई है और जिन लोगों को वहां जगह मिली है उनसे मोटी रकम ली गई है। यह सारे कारण ऐसे हैं जो इस उद्योग को नीचे की ओर ले जा रहे हैं जबकि दुनिया में इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार को चाहिए कि लघु और मध्यम उद्यमियों को वह अपना पूर्ण संरक्षण प्रदान करे और उचित प्रोत्साहन देने का काम करे।

अधिवक्ता संघ नारायणपुर ने किया नव पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का सम्मान

गणेश वैष्णव । सिटी चिफ
नारायणपुर, नारायणपुर न्यायालय में पदस्थ हरेंद्र सिंह नाग अपर सत्र न्यायाधीश नारायणपुर का जेपी देवांगन अधिवक्ता के द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान किया गया। कुमारी प्रतिभा मरकाम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर का सुश्री क्षमा साहू अधिवक्ता के द्वारा पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान किया गया, अधिवक्ता संघ नारायणपुर के सचिव जितेंद्र कुमार शुक्ला के द्वारा शिव प्रकाश त्रिपाठी प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड नारायणपुर का पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान किया गया। न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागणों के मध्य बार एवं बेंच के मध्य एक दूसरे के सहयोग करते हुए सुचारु रूप से मिलकर

न्यायिक कार्य किए जाने के संबंध में बातचीत व चर्चा की गई। इस सम्मान समारोह के दौरान अधिवक्ता जे.पी देवांगन, अधिवक्ता जे.एस. राठौर, अधिवक्ता श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला, अधिवक्ता विक्रम राठौर, अधिवक्ता अविनाश देवांगन, अधिवक्ता चंद्र प्रकाश कश्यप, अधिवक्ता दीपक दास, अधिवक्ता क्षमा साहू, अधिवक्ता दीपिका भंडारी, न्यायालय अधिकारीगण में एडीपीओ चंद्रशेखर राव एवं न्यायालय कर्मचारी गण उपस्थित थे।

इजराइली विदुषी ने की योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण से भेंट

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, पूर्व इजराइली सेनाधिकारी और अब आयुर्वेद विशेषज्ञ, पुरातत्व वैज्ञानिक और योग प्रेमी महिला ओफरा ने मोक्षायतन योग संस्थान योग पहुंचकर योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण से भेंट करके की। वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भारत आई ओफरा ने बताया कि वह 14 वर्ष की उम्र से आयुर्वेद और प्राच्य विद्याओं पर कार्य कर रही है और आयुर्वेद के योग के साथ गहरे संबंध ने उन्हें भारत के लीजेंड योगी और पहले अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत करने वाले गुरु स्वामी भारत भूषण के दर्शन करने

के लिए प्रेरित किया क्योंकि 1990 से ही कुछ इजरायली जिज्ञासु उनके साथ जुड़े हैं। इस अवसर पर मौजूद रहे आयुर्वेद और योग पर कार्यरत कंपनी वेदिकस के संस्थापक आदित्य जैन के साथ मिलकर ओफरा ने योग गुरु के साथ भारत की इन प्राच्य विद्याओं पर चर्चा की। जिसमें गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण ने बताया कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मूलत: एक ही हैं और योग के विस्तार हैं। योग सम्मत जीवन जीते हुए प्रकृति के पंचतत्वों के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर आयुर्वेदिक औषधियां व्याधियों का स्थाई निदान कर पाती हैं। त्यमेकत्र संयमः बताते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य की पीड़ा हरण में इन तीनों के बीच सामंजस्य जरूरी है।ओफरा ने बताया कि वह विगत बीस वर्षों से प्रमाणित आयुर्वेद चिकित्सक हैं और दुनिया के अनेक देशों में आयुर्वेद का प्रचार करने में जुटी हैं। ओफरा ने बताया कि गुरुदेव के सान्निध्य से वह बहुत प्रभावित हुई और उनके साथ चर्चा करके हमे सिर्फ समाधान ही नहीं मिला बल्कि और अधिक कुछ करने की प्रेरणा भी मिली।

मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति का विवरण अपलोड नहीं करने वाले कार्मिकों का रोका

जाएगा वेतन, नहीं होगी पदोन्नति – मण्डलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद

मण्डलायुक्त ने तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, मण्डलायुक्त डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने मण्डल के तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि 31 जनवरी 2025 तक मण्डल के समस्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराना सुनिश्चित करें। डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि 31 दिसम्बर 2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार पोर्टल पर विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा क्रियाशील हो गई है। निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर विवरण प्रस्तुत न करने पर इसे प्रतिकूल रूप से लिया जाएगा तथा 01 फरवरी 2025 के पश्चात होने

वाली विभागीय चयन समिति के बैठकों में ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
मण्डलायुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त राज्य कार्मिकों का मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। ऐसे राज्य कार्मिक जिनके द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर निर्धारित समय तक अपलोड नहीं किया जाएगा उनका वेतन रोकते हुए विभागीय कार्यवाही कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आगाह जंगल में ध्वनि प्रदूषण एवं उत्पातियों पैनी नजर

नए साल में कही भारी ना पड़ जाए शौक, होगी कार्यवाही

उमरिया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया (कोर जोन / बफर जोन) उमरिया अन्तर्गत ईकों सेंसिटीव जोन, अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र आता है । बांधवगढ़ टाइगर रिवर्ज में ताला, मगधी, खितौली, धमोखर, पनपथा एवं जोहिला पर्यटन जोन संचालित है। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत बने स्थलों में कई पर्यटन ईकाईयों होटल/रिसोर्ट/लॉज /ढावा आदि संचालित है। दीपावली त्यौहार के बाद पर्यटन गेट से लगे ग्रामों में संचालित होटल/रिसोर्ट / लॉज में डेस्टीनेशन वेडिंग / वैवाहिक कार्यक्रम संम्पादित किये जाते है एवं इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष नववर्ष के आगमन पर नववर्ष का पर्व मनाया जाता है। जिसमें भी अत्यधिक तेज ध्वनि, वाद्ययंत्रों, डी.जे. में तीव्र ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अतिशवाजी / तेज ध्वनि लाइटों, रंग बिरंगी लाइटों का उपयोग किया जाता है। जिससे वन्यजीवों के रहवास, प्राकृतिक जीवनयापन एवं उनके दैनिक कियाकलापों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, एवं उनके मानसिक संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन के क्षेत्रों में वन प्राणियों की प्रचुरता है ।

जंगल में भारी पड़ेगा उपद्रव...
वनक्षेत्रों में आवागमन हेतु मार्ग संचालित है। जिसमें वाहन चालक द्वारा रोड पर अत्याधिक तेज गति से वाहन चलाये जाते है जिससे वन्यप्राणियों से दुर्घटना होकर वन्यप्राणियों की मृत्यु एवं जनहानि / घायल होने की प्रचुर संभावना होती है। साथ ही इस अवधि के दौरान क्षेत्र में सड़क पर/जंगल/नदी के समीप किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधि / उपद्राव/पार्टी / शराब पीकर गाड़ी चलाने अथवा किसी भी

प्रकार की गतिविधि जिससे आमजन तथा सैलानियों को असुविधा/समस्या न हो तथा वन प्राणियों दैनिक के कियाकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पटाखे और आवाज पर पाबन्दी...
उप संचालक बांधवगढ टाईगर रिजर्व पीके वर्मा ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कोरजोन एवं बफरजोन तथा चिन्हित ईको सिंसेटिव जोन, अतिरिक्त संवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र के समीप वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी या चलित वाहन आदि में टीव्ही, एल.सी.डी. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग 5 जनवरी 2025 की सायं 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित किया है।

दवा सेवक, दवा का सेवन अपने समक्ष में कराएं- अपर कलेक्टर

सामूहिक दवा 10 फरवरी से 25 फरवरी तक का सेवन

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ उमरिया, फाईलेरिया हाथीपांव रोकथाम हेतु 10 फरवरी से 25 फरवरी तक उमरिया जिले में 2 साल से उपर की समस्त आबादी को आईवरमेक्टिन, डीईसी एवं एलवेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाना है । कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम ने कहा कि 10,11,13 एवं 14 फरवरी को बूथ बनाकर स्कूंल, कालेज, एवं हॉस्टल में दवा का सेवन कराएं इसके साथ ही 15, 17, 18, 19, 20 एवं 21 फरवरी को घर घर भ्रमण करके दवा का सेवन कराएं । अगाामी 22 फरवरी से 25 फरवरी तक छुटे हुए लोगों को दवा का सेवन कराएं। दवा सेवक, दवा का सेवन अपने समक्ष में कराएं , दवा व्यक्ति को देकर नही आएं।

गोली की उंचाई होगा मानक.. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डॉ. एस.बी. चौधरी ने अवगत कराया कि इस वर्ष जिले के 03 ब्लॉक करकेली, मानपुर, पाली एवं शहरी क्षेत्र उमरिया में दवा सेवन कराया जायेगा। दवा सेवन कराने की समस्त तैयारियॉ जारी है। उन्होने बताया कि कि 2 वर्ष से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को 100 मिलीग्राम डीईसी की 1 गोली, 1 एलवेंडाजोल की गोली , 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को 200 मिली की 2 गोली, एक गोली एलवेंडाजोल तथा 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों को 300 मिलीग्राम की 3 गोली डीईसी तथा 1 गोली एलवेंडाजोल की खिलाई जाएगी । इसी तरह आरईवर मेक्टिन गोली की उंचाई के अनुसार खिलाई जाएगी ।

घबराए नहीं अस्पताल आये... डीईसी गोली दो साल से ऊपर की आयु के लोगो को खिलाई जाएगी । आईवरमेक्टिन की गोली पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को नही खिलाई जाएगी । गर्भवती माताओं, अत्याधिक वृध्द, गंभीर रोगों से पीडित व्यक्ति गोली नही खाएं। गोली खाली पेट नही खाना है । गोली के प्रतिकूल प्रभाव नही है, फिर भी अगर किसी के शरीर में माइक्रो फाईलेरिया के कीटाणु होते है दवा के सेवन से नष्ट होने पर अनुशंगी प्रभाव होते है जिसमें सिरदर्द, बदनदर्द, पेटदर्द, उल्टी आदि शामिल है । ऐसे नजदीक के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, प्राथमिक स्वा0 केंद्र से संपर्क कर आवश्य्क दवा प्राप्त करें। इससे घबराएं नही यह क्षणिक होता है व मरीज स्वत: ठीक हो जाता है । आपकी सक्रियता से ही फाईलेरिया की रोकथाम संभव है ।

पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध... डॉ. देवेन्द्र तोमर डब्ल्यू.एच.ओ. स्टेट कोआर्डिनेटर द्वारा एम.डी.ए. कार्यक्रम का प्रेजेन्टेशन दिया गया एवं विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु कहा गया एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. व्ही.एस. चंदेल ने बताया है कि ब्लॉकों में डी.ई.सी. गोली 1942779 लाख, आईवर मैक्टिन 1942779 लाख एवं एल्वेन्डाजोल 971400 लाख गोली की आवश्यकता होगी। जो जिले मे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिन्हे ब्लॉक से दवा सेवक के पास तक पहुचॉ दिया जायेगा। दवा सेवन के उपरांत अनुसंगी प्रभाव हेतु दवाओं की किट भी प्रदाय की जावेगी। दवा पूर्णत: सुरक्षित है। जिन किसी भी व्यक्ति को दवा सेवन के बाद बुखार, उल्टी, सिर दर्द, बदन दर्द होता है तो वो घबरायें नहीं, यह क्षणिक होता है और स्वत: ही ठीक हो जाता है। यह उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनके अंदर फायलेरिया के किटाणु होते हैं। जो दवा खाने पर मर जाते है। एल्बेन्डाजो गोली को चबा-चबा कर खिलाये जाना हैं। बैठक में डिप्टी कलेक्टर मीनांक्षी इंगले हरनीत कौर, अंबिकेश प्रताप सिंह सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन की नाक के निचे बेजा अतिक्रमण, फेल जिला सरकार

नियमविरुद्ध लगा बिजली कनेक्शन, रातो रात खुद गया ट्यूबवेल

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ शहडोल, संपूर्ण जिले भर में भू माफियाओं की संलिप्तता संभवत: किसी से छिपी नहीं है। उनके द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन करने को लेकर बेखौफ ठेंगा दिखाना और मनमानी व अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना, मानो इस जिले में अब आम बात हो चली है। वहीं दूसरी ओर यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि, प्रशासनिक जिम्मेदार भी इन मामलों को लेकर कोई कार्रवाई या पहल करने सरोकार नहीं रखते। परिणाम स्वरूप आज यह स्थिति निर्मित है कि, मनमाने तर्ज पर भू-माफिया अपनी कर रहे हैं। कहीं किसी गरीब की जमीन पर अवैध कब्जा, तो कहीं शासकीय भूमि को हेरफेर कर क्रय-विक्रय का खेल, कहीं किसी जमीन के फर्जी कागजात बन जाने जैसे कई मामले आए दिन सामने आते रहे हैं। विचारणीय है कि, अधिकांश मामलों में ठोस दस्तावेजों सहित शिकायत बावजूद आज भी कार्रवाई मूर्तरूप नहीं ले सकी है। जिसके चलते जहां शिकायतकर्ता या पीड़ित इंतजार की घड़ियां गिन रहा है तो वहीं दूसरी ओर भू-माफिया चांदी काट रहे हैं।

हांथीडोल का मामला.. ऐसा ही एक ताजा मामला कोयलांचल क्षेत्र के धनपुरी नगर से प्रकाश में आया है। जहां स्थित शासकीय आराजी को ही भू-माफिया ने बेचने का कारनामा कर दिखाया है। उक्त मामले की शिकायत कर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग भी की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि, धनपुरी नगर पालिका अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 2 (हाथीडोल) के शासकीय भूमि, खसरा क्रमांक 161/2 व रकबा 0.267 में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है और विक्रय कर दिया है।

झोपड़ी के आड़ में जुगाड़... मामले में मिली जानकारी के अनुसार उक्त भूमि को कल्लू बैसाखू नामक व्यक्ति ने भू-माफिया रवि केवट को बेचा दिया है। यह भूमि खैरहा हरदी रोड़ में स्थित बताई गई है। विचारणीय है, उक्त आराजी की भूमि पर झोपड़ीनुमा घर बनाकर भू-माफिया ने वहां बकायदे ट्यूबवेल भी लगवा लिया है। इतना ही नहीं उसने बकायदा यहां पर विद्युत कनेक्शन ले, सुविधा का लाभ उठा रहा है।

लापरवाही या माफ़िया हुए उपकृत... गौरतलब है कि, उक्त शासकीय भूमि पर बेधड़क रूप से बोर करवाना और विद्युत कनेक्शन करवा लेना, जहां भू-माफिया की दबंगई का प्रतीक है। तो दूसरी ओर यह प्रशासनिक जिम्मेदारों की निष्क्रियता व घोर लापरवाही को भी प्रदर्शित करता है। उपरोक्त सुविधाएं जिस तरीके से प्राप्त हुई हैं, निश्चित ही उससे कई अन्य गंभीर सवालता उठ खड़े होते हैं। जिसका जबाब शायद जिम्मेदारों से ही मिल सकता है। बहरहाल, उक्त शासकीय आराजी की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की गई है। देखना यह होगा कि, यह भूमि कब तक और किस तरह से अतिक्रमण मुक्त हो पाती है..?

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे के घर ईडी की रेड

भ्रष्टाचार के आरोपों पर मचा बवाल

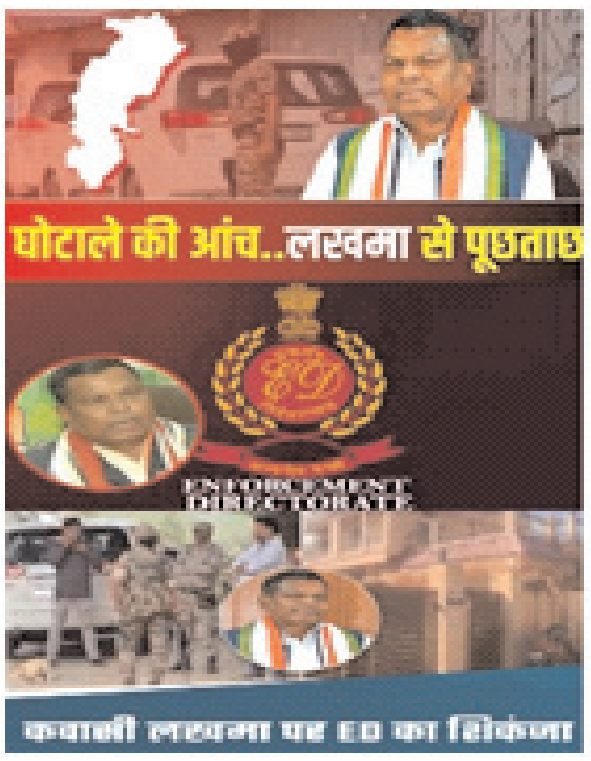

राजीव खरे ।सिटी चीफ रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाली खबर ज़ोरों पर चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में राज्य के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे के घर छापा मारा। ईडी ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम दस्तावेज और सबूत बरामद हुए हैं। ये सबूत आबकारी विभाग में व्यापक अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। माना जा रहा है कि इन आरोपों के आधार पर कवासी लखमा की गिरफ्तारी संभव है।

ईडी की छानबीन में यह आरोप लगाया गया है कि कवासी लखमा के कार्यकाल के दौरान शराब माफिया और ठेकेदारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। रेड के दौरान कई वित्तीय दस्तावेज, संदिग्ध लेन-देन का रिकॉर्ड, और संपत्ति से जुड़ी जानकारी बरामद की गई है।

कवासी लखमा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा, मैं अनपढ़ हूं। अधिकारियों और ठेकेदारों ने मुझे मूर्ख बनाकर फाइलों पर साइन करवा लिए। मैंने कभी किसी गलत काम में हिस्सा नहीं लिया।

हालांकि, सवाल उठता है कि जब कवासी लखमा सत्ता में थे और तमाम सरकारी सुविधाओं और ऐशो-आराम का लाभ उठा रहे थे, तब उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा कि अधिकारी और ठेकेदार उन्हें उपकृत क्यों कर रहे थे? क्या यह संभव है कि उन्हें यह पता नहीं था कि उनके नाम पर ये लोग कितना लाभ उठा रहे होंगे ।

इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में गर्मागर्मी पैदा कर दी है। भाजपा ने इस पर तीखा हमला करते हुए कहा, कवासी लखमा की अनपढ़ होने की दलील स्वीकार्य नहीं है। जब वे सत्ता के मजे ले रहे थे, तब उन्हें यह समझना चाहिए था कि यह सब क्यों हो रहा है। यह कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों का परिणाम है।वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को केंद्र सरकार की साजिश करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, यह पूरी तरह से विपक्षी नेताओं को बदनाम करने का प्रयास है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

ईडी अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। राज्य की जनता और राजनीतिक दल इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। यह मामला न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति बल्कि देशभर में भ्रष्टाचार पर एक बड़ी बहस छेड़ने वाला है।

ओपी चौधरी: बचपन से राजनीति तक की प्रेरणादायक यात्रा

राजीव खरे ।सिटी चीफ रायपुर, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की कहानी संघर्ष, समर्पण और समाजसेवा की मिसाल है। एक साधारण परिवार से लेकर आईएएस अधिकारी और फिर एक सफल राजनीतिज्ञ बनने तक का उनका सफर न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

ओपी चौधरी का जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार कृषि कार्य पर निर्भर था। सीमित संसाधनों के बावजूद, उनके माता-पिता ने शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से ही ओपी चौधरी पढ़ाई में होशियार थे और बड़ी सोच रखते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रायपुर के साइंस कॉलेज से स्नातक किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें 2005 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की परीक्षा में सफलता दिलाई। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ कैडर में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली और समाजसेवा के प्रति समर्पण से जनता के बीच पहचान बनाई।

ओपी चौधरी की कलेक्टर के रूप में तैनाती ने कई नई परंपराओं की शुरुआत की।

दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने गीदम में बच्चों के लिए रोजगार उन्मुखी शिक्षा केंद्र शुरू किया। यह पहल आदिवासी बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। उनकी इस योजना ने हजारों बच्चों का भविष्य संवारने में मदद की।रायपुर में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने एक छात्रा को एक दिन का कलेक्टर बनने का अवसर दिया। इस अनोखी पहल ने प्रशासन के प्रति युवाओं को प्रेरित किया और समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। उन्होंने दंतेवाड़ा में 'एजुकेशन सिटी' प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना था।

दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। 2011 में 'प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया तथा शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान को लेकर कई पुरस्कार भी मिले।

2018 में ओपी चौधरी ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े और समाजसेवा के अपने उद्देश्य को राजनीति के जरिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अपने पहले प्रयास में हालाँकि वह विधानसभा चुनाव हार गए पर तब कांग्रेस की लहर थी। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ़ उन्होंने जीत हासिल की बल्कि उन्हें वित्त मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद मिला।

2023 में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के बजट में विकास और समावेशिता को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में राज्य ने वित्तीय स्थिरता, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन का पालन के लिये कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। राज्य ने अपने वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में सफलता पाई। इसके लिये छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को मुख्यमंत्री के साथ समन्वय कर अपने विजन और नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने व कुशल वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार ने हाल ही में सराहना भी की। राज्य की 25वीं वर्षगांठ को 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाने की उनकी पहल राज्य में अधोसंरचना के विकास को दर्शाती है।

ओपी चौधरी अपने सादगीपूर्ण जीवन और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा और रोजगार समाज के विकास के मुख्य स्तंभ हैं। उनके सभी प्रयास इसी दिशा में केंद्रित रहे हैं। ओपी चौधरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सीमित संसाधन कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते, यदि समर्पण और मेहनत का साथ हो। उनकी यात्रा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। वे एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने जनता की समस्याओं को न केवल समझा, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए।

मुख्य मंत्री के आदेश की हुई अवहेलना नहीं मिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कर्मचारियों को समय पर वेतन

यशपाल सिंह जाट । सिटी चीफ अनुपपुर, अनुपपुर अनुपपुर जिले में मुख्य मंत्री के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीनस्त कर्मचारियों को आज दिनांक 3/1/2025 तक वेतन नहीं मिल पाया है ज्ञात हो कि मुख्य मंत्री महोदय का आदेश था कि वेतन हर माह की 1 तारीख को सभी कर्मचारियों के खाते में आ जाना चाहिए था मगर इसका पालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में नहीं हुआ और आज दिनांक3/01/2025 तक इस कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन का आहरण नहीं हो पाया है जिससे इस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कई कर्मचारियों के बैंक लोन की किस्त बाउंस हुई एवं उन्हें अब बैंक को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा साथ ही उनकी लोन की किस्त समय पर न चूकने के कारण उनके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, अभी हाल में ही नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का पद ग्रहण करने वाले नए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ वर्मा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिसके कारण वेतन आहरण में देरी हुई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की इस लापरपाही का नतीजा उनके अधीनस्त कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है क्या अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने कर्मचारियों के इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे नहीं कर सकते पर इनकी लापरवाही से कर्मचारियों को मोटी रकम के साथ साथ किस्त न चुका पाने के कारण जो मानसिक कष्ट हुआ उसका जिम्मेदार कौन है और उसकी भरपाई कैसे होगी।

गाँधी सागर बाँध प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर केक कट कर मनाया गया संविदा नियुक्ति मुख्य अभियंता उज्जैन द्वारा जन्मदिन सेलिब्रेशन

उज्जैन नए वर्ष के अवसर पर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने का मामला वृहद बांध गाँधी सागर जिला मंदसौर में देखने को मिला है जहाँ पर भारतीय कानून एवं रक्षा कानून एवं मध्यप्रदेश लोक सुरक्षा अधिनियम 1959 के तहत संरक्षित क्षेत्र / प्रतिबंधित क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता उज्जैन तेजकरण परमार द्वारा बाँध के जिम्मेदार विभागीय अधिकारियो की उपस्थिति में उनके संबंधी का जन्मदिन नववर्ष की संध्या एवं रात्रि समय में वृहद बाँध के पर गेट मशीनरी हेतु निर्मित कमरे के टॉप पर टेबल कुर्सी लगाकर केक कट करते हुए मनाया गया एवं फोटोज को स्टेटस पर डालते हुए उक्त कृत्य को महिमामंडित करना पाया गया है ; जबकि उपरोक्त मुख्य अभियंता विभाग से सेवानिवृत हो चुके है एवं वर्तमान में संविदा नियुक्ति के दम पर अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल रतलाम एवं मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग उज्जैन के प्रभार का दायित्व निर्वाह कर रहे है ; यहाँ यह विदित हो कि उपरोक्त बांध राष्ट्रिय संपत्ति है एवं भारतीय कानून एवं रक्षा कानून एवं मध्यप्रदेश लोक सुरक्षा अधिनियम 1959 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित है ; शासकीय संपत्ति का इस प्रकार से निजी कार्य हेतु दुरूपयोग का उदाहरण वृहद बाँध की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है साथ ही बाँध के प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं स्टाफ की उपरोक्त कृत्यों में संलिप्तता को उजागर करता है जो विभाग के नियमित कर्मचारी होकर भी संविदा नियुक्ति वाले अधिकारी की इच्छा पूर्ति हेतु नियमों को ताक पर रख कर उन्हें खुश करने में लगे रहते है ढ इस दौरान प्रभारी उपयंत्री राजेंद्र महाजन एवं विद्युत जल संभाग उज्जैन के कार्यपालन यंत्री एन पी सोलंकी अपने परिवार सहित उपस्थित थे । परन्तु वे नियमो का ध्यान रखने में असफल रहे ओर उपरोक्त कृत्य के गवाह बनते रहे ढ इस संबंध में कार्यपालन यंत्री श्री सी एस चरावण्डे से संपर्क करने की कोशिश की गयी पर समाचार लिखे जाने तक उनसे संपर्क नही हो पाया है। भविष्य में उपरोक्त कृत्यों की पुनरावृति रोकने हेतु शासन को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है ।

आज होगा सरस्वती शिशु मंदिर पिपलियामंडी में मारो हृदय मालवा विषय पर रंगमंचीय कार्यक्रम

पिपलियामंडी – नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा आकर्षक रंग मंचीय कार्यक्रम एवं विद्या भारती के 5 आधारभुत विषयो का प्रकट कार्यक्रम आयोजित होगा ! विद्यालय के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि आज विद्या भारती की योजनानुसार %म्हारो हृदय मालवा% विषय पर आकर्षक रंगमंचीय कार्यक्रम आयोजित होगा कार्यक्रम मे राज्य सभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सुंदरलाल शर्मा, सह प्रान्त प्रमुख, राघवेंद्र देरा, विभाग समन्वयक मंदसौर विभाग का मुख्य आतीथ्य प्राप्त होगा ! एवं भैया बहिनों द्वारा आकृषक रंग मंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा ! एवं आगामी 3 जनवरी को विद्या भारती के 5 आधारभुत विषयो का प्रकट कार्यक्रम भी आयोजित होगा ! जिसमे विद्या भारती मालवा प्रान्त के संघठन मंत्री आदरणीय योगेश शर्मा समाज सेवी जगदीश लोहार, नगर परिषद अध्यक्ष महोदया श्रीमती इंदिरा सुनील देवरिया के मुख्य आतीथ्य मे सम्पन्न होगा उक्त कार्यक्रम मे शिशु वाटिका की

आकर्षिक प्रदर्शनी एवं नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा योग शिक्षा शारीरिक शिक्षा संगीत शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा से जुडी हई प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाएगी विद्यालय अध्यक्ष महोदया सचिव महोदय प्राचार्य प्रधानाचार्य एवं समस्त आचार्य परिवार ने उक्त कार्यक्रम मे समाज जनो की सहभागिता की अपील की !

मोह माया को छोड़कर वृंदावन से प्रेम करो जीवन तर जायेगा - पं. उपाध्याय

उज्जैन

हम अगर पड़ लिख जाएं तो माता पिता गुरु को भूल जाते है उनका आदर करना झुकना छोड़ देते हे । जो मनुष्य वृंदावन जाकर भी प्रेम करना ना सुख पाते उनका जीवन व्यर्थ है । यह बात आक्याजागीर के श्रीराम मंदिर के प्रांगण में बाबा गंगा दास जी महाराज की पुण्यतिथि पर चल रही तीन दिवसीय राधा रानी जीवन प्रसंग की कथा में कथा वाचक पंडित श्री रविराज उपाध्याय ने कही । उन्होंने कहा कि संसार में ठाकुर जी से प्रेम करना सीखो ताकि जीवन

भवसागर तर जाए । दुनिया के लोगो से प्रेम करोगे तो वह मोह माया में ले डूबेगा । इसलिए सांसारिक मोह से दूर होकर परमात्मा से लगन लगालो । वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण और राधा रानी का वास समाया है । मन से ब्रज का भ्रमण जरूर करना चाहिए। कथा के प्रारंभ में श्री मद भागवत पोथी की शोभायात्रा निकाली जिसमे मंदिर के पुजारी महंत अवध बिहारी दास जी महाराज, गांव के वसूली पटेल धुलजी पटेल सहित ग्रामीण जन शामिल हुए । कथा का समापन आगामी 4 जनवरी को होगा इस अवसर पर बाबा गंगा दास जी महाराज की समाधि का पूजन होगा और श्रीराम दरबार ने छप्पन भोग लगाया जाएगा । इस कार्यक्रम में देशभर के अनेक राज्यों से साधु संतो का आगमन होगा ।

38 वर्ष बेदाग शासकीय सेवा कर निवृत्त हुए रमेशचंद्र हिहोर का भोला भण्डारा परिवार ने किया सम्मान

हिहोरजी के शिक्षा क्षेत्र में योगदान को सदा याद रखा जाएगा – नाहर

झाबुआ

थांदला। हर व्यक्ति का सपना देश व समाज की सेवा का होता है जिसे खुशनसीब इंसान ही पूरा कर पाता है ऐसे ही इंसान है थांदला के रहने वाले रमेशचन्द्र हिहोर जो इस वनांचल में सहायक शिक्षक के पद पर रहकर ग्रामीण आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ शासकीय सेवा के 38 वर्ष पूर्ण कर सेवा निवृत्त हुए। इस अवसर पर उनके परिजनों ने उनके उत्कृष्ट कार्यों व पारिवारिक जिम्मेदारियों के कुशल निर्वहन में उनके योगदान को याद करते हुए उनकी सेवा निवृत्ति का भव्य आयोजन रखा। आयोजन उनके निज निवास शांति कालोनी में पूजा पाठ के साथ रखा गया जहाँ उनके सहचर्य कर्मचारियों के अलावा इष्ट मित्रों ने आकर उनकी कुशल शांतिपूर्ण शासकीय सेवा निवृत्ति की बधाई देते हुए उनके शेष

पारिवारिक जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भोला भण्डारा परिवार के श्रीमंत अरोड़ा, तुलसी मेहते, दिनेश चतुर्वेदी, राजू धानक, मोहनलाल चौहान, मनोज उपाध्याय, आत्माराम शर्मा, पवन नाहर, मिश्रीलाल मालवीय, मनोहरदास चौहान, मोहनलाल चौहान, मनीष जैन, मनीष अहिरवार, राकेश जोझा, नीरज सौलंकी, विवेक व्यास, अनिल पाठक आदि ने उपस्थित होकर उन्हें शाल माला पहनाकर महाकाल की तस्वीर भेंट करते हुए बधाई दी। उल्लेखनीय है कि भोला भण्डारा परिवार से जुड़कर सेवा कार्यों में अग्रणी रहने वाले हिहोरजी मेघनगर विकासखंड में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ थे जो 31 दिसम्बर 2024 को सेवा निवृत्त हो गए है। इनके सफल शासकीय सेवा कार्यों के लिए उन्हें बधाई देते हुए भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के प्रदेश सचिव पवन नाहर ने कहा कि वनांचल में आदिवासियों को समझाइश देते हुए उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना चुनोती पूर्ण होता है ऐसे में हिहोरजी ने करीब 38 वर्ष पूर्व अभावों में प्रभावी कार्य किये है जो सराहनीय है। अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हिहोर बाउजी को उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सदा याद किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिजनों में लक्ष्मणसिंह, गलसिंह, दलसिंह, मानिया, राकेश, दिनेश, लल्लु, सुरेश, मोहन, सुकीया, अमरसिंह, राजेश, कमलेश, महेश, विजय, संजय के साथ नन्हें आयुष व कोणार्क सहित समस्त हिहोर परिवार को उनके ऐतिहासिक निवृत्ति आयोजन के लिए बधाई दी।

नव वर्ष के मौके पर बड़ी संख्या मैं मेले पहुंचे लोग

सुरक्षा को लेकर मेले में रहेगी तीसरी आंख की नजर

खरगोन कसरावद- नगर का मेला अपने रंग में दिखाई दे रहा है। नए साल मे श्री गांगलेश्वर महादेव मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान बच्चों एवं बड़ों ने जहां सतरंगी रोशनियों के बीच सेल्फी तथा ग्रुप फोटो के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद लिया। वही खानपान की दुकानों पर लजीज व्यंजनों का लुफ्त उठाया। मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर इस बार खास ध्यान दिया जा रहा है मेला क्षेत्र में निगरानी के लिए 8 से 10 पॉइंट पर सीसीटीवी

कैमरे लगाए गए हैं नगर परिषद ने कैमरे लगाकर एक कंट्रोल रूम बनाया। नगर परिषद अधिकारी कमलेश गोले ने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए कैमरे को मेला क्षेत्र में बने अस्थाई कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है । एवं पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है यहां कैमरे आसपास की हर हल-चल टीवी पर दिख रहा है।

ईव्हीएम गोडाउन का निरीक्षण

विदिशा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रौशन कुमार सिंह ने आज दो जनवरी को ईव्हीएम गोडाउन का निरीक्षण किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मासिक रूटीन कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा आज ईव्हीएम गोडाउन का निरीक्षण किया गया है।

कलेक्टर ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दिए टिप्स

सीहोर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा के संबंध में टिप्स देते हुए कहा कि हमें अपना टाइम टेबल बनाकर पूरी लगन से उस पर काम करना चाहिए। यदि हम स्वयं के द्वारा बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करते है और निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलती है। उन्होंने कहा कि विषयों को याद रखने के लिए हमें पढ़ाई को घटनाओं से

जोड़कर अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी क्षमताओं को ठीक से समझते हुए किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहिए और पढ़ाई को अधिकतम समय देना चाहिए। यह मार्गदर्शन टाउन हॉल सीहोर स्थित लाइब्रेरी में संचालित आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा कोचिंग संस्था के विद्यार्थियों को दिए। उल्लेखनीय है कि आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा द्वारा सीहोर के टाउन हॉल स्थित लाइब्रेरी में यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस प्रतिदिन सुबह 8:00 से 10:00 तक संचालित की जा रही हैं।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुआ राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्र-गान जन-गण-मन का सामूहिक गायन

गुना

कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की उपस्थिति में राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्र-गान जन गण मन का सामूहिक गायन गुरूवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में हुआ। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर संजीव खेमरिया, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा सहित विभिन्न विभागों अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

विधान सभावार विजन आधारित तैयार करें रोडमैप - मुख्यमंत्री डॉ.यादव

जन समस्याओं के निराकरण के लिए करें जन-संवाद

रैन बसेरों का निरीक्षण करें

विधानसभा वार समीक्षा की जाए

इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए निर्देश

इंदौर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट (रोडमैप) बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विधायक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण को लेकर जन-संवाद करें। जनकल्याण अभियान के मिल रहे परिणामों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं जानें और निराकरण के लिए तुरन्त कदम उठाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों एवं वृहद् निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, इंदौर सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य क्षेत्रीय विधायकों एवं जन-प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने-अपने क्षेत्र से वर्चुअली सहभागिता की। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एस.एन, मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गाँव में रात्रि विश्राम करें अधिकारी और जन-प्रतिनिधिमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वुर्चअली जुड़े मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए अधिकाधिक फील्ड दौरे करें। जन-प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ दूरस्थ गाँव (विशेषकर जनजातीय ग्राम) में रात्रि विश्राम करें। वहां ग्रामीणों से बात करें, उनकी कठिनाईयों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने दिन-ब-दिन बढ़ती सर्दी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें। जरूरतमंदों को कंबल एवं गर्म वस्त्र प्रदाय करें। किसी को भी सर्दी से कठिनाई न होने पाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए विधायक यदि चाहें, तो कोई नवाचार भी कर सकते हैं। ऐसी नवाचारी गतिविधियों को अमल में लाएं, जिससे जनता को अधिकतम लाभ हो। उन्होंने कहा कि अब सभी संभागों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव जिलेवार समीक्षा बैठक करेंगे। इससे सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों एवं संवदेनशील विषयों को रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स अब विधानसभावार समीक्षा बैठक करें। जिले के सभी विधायकों से चर्चा करें और उनके विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट बनाने में सहयोग भी करें।**पुराने मंजूर सीएम राइज स्कूल का निर्माण पूरा कराएं** मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की समीक्षा में कहा कि पुराने मंजूर सीएम राइज स्कूलों का जितना भी निर्माण कार्य अभी शेष है, पहले उन्हें विशेष प्राथमिकता से पूरा कर लिया जाए। इसके बाद नये सीएम राइज स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव लिये जाए।

चीन में नए वायरस ने मचाया हाहाकार!

अब तक 170 लोगों की मौत, लग गया आपातकाल?

इन्टरनेशनल डेस्क. चीन में एक बार फिर से वायरस का प्रकोप गहराता जा रहा है। अस्पतालों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति बन गई है। इस बार ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सरकारी और वैज्ञानिक एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, वायरस से अब तक चीन में 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 देशों में इसके 7,834 मामले दर्ज किए गए हैं।

WHO ने किया वैश्विक आपातकाल घोषित

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह वायरस तेजी से फैल रहा है, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि चीन ने पहली बार 31 दिसंबर, 2019 को स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की थी।

क्या है ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस

ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस पहली बार 2001 में खोजा गया था। यह मुख्य रूप से 14 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है। वायरस मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम में फैलता है और खांसी, बुखार, और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। चीन के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन ने लैब रिपोर्टिंग प्रक्रिया को तेज कर दिया है और संक्रमित मरीजों की निगरानी शुरू कर दी है।

संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं हाल ही में रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि 16 से 22 दिसंबर के बीच संक्रमण की दर में तेजी आई है। यह वायरस उन क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है, जहां तापमान तेजी से गिर रहा है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और रिपोर्ट्स ने इस संकट को और अधिक उजागर कर दिया है।

आपातकालीन घोषणाओं का इतिहास

WHO की समिति, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न , ने अब तक छह बार आपातकालीन स्थिति घोषित की है। समिति प्रमुख डिडियर हौसिन ने कहा कि इस बार का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। पहले के आपातकालीन मामलों में इबोला, स्वाइन फ्लू और कोविड-19 शामिल हैं।

स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास

चीन सरकार ने अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार करने, वायरस की जांच बढ़ाने, और जनता को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू कर दिए हैं। WHO ने भी इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर में अलार्म बजा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस संकट को रोका जा सके। सभी को सतर्क रहने और आवश्यक स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

भूकंप के तेज झटकों से थर्राया चिली

रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता

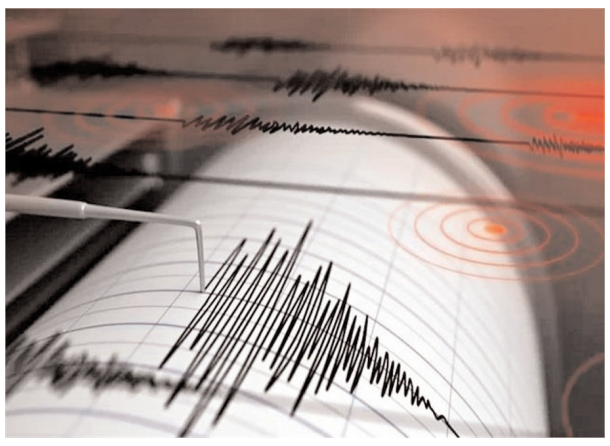

इंटरनेशनल डेस्क: गुरुवार को चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। यूरोपीय-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (श्वस्ष्ट) के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 104 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। गहराई के बावजूद, भूकंप के झटके क्षेत्र में स्पष्ट रूप से महसूस किए गए।

नागरिकों को सतर्क रहने की अपील

हालांकि, अब तक किसी बड़ी हानि या जनहानि की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की अपील की है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखते हुए संभावित आफ्टरशॉक्स को लेकर भी चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार, भूकंप के बाद आमतौर पर आफ्टरशॉक का खतरा रहता है, जो कभी-कभी मुख्य भूकंप जितना ही प्रभावी हो सकता है।

चिलीः भूकंप-प्रवण क्षेत्र

चिली भूकंप-प्रवण देशों में से एक है, जहां प्लेट टेक्टॉनिक्स के कारण अक्सर भूकंप आते हैं। इतिहास में यहां कई भीषण भूकंप दर्ज किए गए हैं। 1960 में वल्डिविया में आया 9.5 तीव्रता का भूकंप अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। इसी प्रकार, 2010 में कोंसेप्सियन में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी।

छोटे झटकों को मानें चेतावनी

विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे भूकंप अक्सर बड़े भूकंप से पहले संकेत देते हैं। हालांकि, भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 2005 का कश्मीर भूकंप इसका एक उदाहरण है। 7.6 तीव्रता के इस भूकंप ने पाकिस्तान और भारत के कश्मीर क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 80,000 से अधिक लोगों की जान गई थी।

आपदा प्रबंधन एजेंसियां सतर्क

चिली सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं। स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर बने रहने, अनावश्यक यात्रा न करने, और सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे चल रही मोदी सरकार

CPI नेता डी राजा ने कहा- देश को फासीवाद की ओर धकेल रही..

पटना. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद डी. राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को पूंजीवाद का समर्थक बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे चल रही है।

नीतीश कुमार और नायडू के समर्थन से ही चल रही मोदी सरकार

राजा ने गुरुवार को यहां भाकपा के शताब्दी समारोह और पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय महासचिव ए. बी. वर्धन की 10वीं जयंती के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि मोदी सरकार नीतीश कुमार और नायडू के समर्थन से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि कुमार ने भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए पटना में बैठक आयोजित की थी, लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से भाजपा से हाथ मिला लिया और अब उसी के समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे हैं। भाकपा महासचिव ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को फासीवाद की ओर धकेल रही है और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाह के आचरण के कारण उन्हें गृह मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

केंद्र सरकार अडानी के हित में फैसले ले रही

राजा ने केंद्र सरकार को पूंजीवाद का समर्थक बताया और कहा कि केंद्र सरकार अडानी के हित में फैसले ले रही है। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर भी बात की और आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी का संकट गहरा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे रायों में प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। भाकपा नेता ने कार्यकर्ताओं से बिहार में पार्टी को मजबूत करने की अपील की ताकि भाजपा को बिहार और केंद्र से उखाड़ फेंका जा सके। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र नाथ ओझा ने भी केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान शासन में संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में सहयोग की अपील की। भाकपा के राय सचिव रामनरेश पांडेय ने वामपंथी दलों से एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का सुझाव दिया।

भारत में बढ़ रहा गर्भाशय निकालने का चलन, 5% महिलाओं ने कराई सर्जरी

नेशनल डेस्क. भारत में महिलाओं के बीच हिस्टेरेक्टामी (गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन) की बढ़ती प्रवृत्ति पर एक अध्ययन ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। देश में लगभग 5 प्रतिशत महिलाओं ने यह ऑपरेशन करवाया है। यह जानकारी वर्ष 2015-16 के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आई है।

अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के चौथे चरण में 25-49 वर्ष की 4.5 लाख से अधिक महिलाओं के आंकड़ों का अध्ययन किया।

हिस्टेरेक्टामी का प्रसारः 25-49 वर्ष की आयु की 4.8 प्रतिशत महिलाओं ने यह सर्जरी कराई है। प्रत्येक 100 में से लगभग 5 महिलाओं ने गर्भाशय निकलवाने का ऑपरेशन करवाया।

मुख्य कारणः मासिक धर्म के दौरान भारी रक्तस्राव सबसे आम समस्या रही।

व्यवसाय के अनुसार जोखिमः कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं में अन्य महिलाओं की तुलना में यह सर्जरी करवाने की संभावना 32 प्रतिशत अधिक पाई गई।

राज्यवार स्थितिः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में हिस्टेरेक्टामी की दरें सबसे अधिक रहीं। वहीं बिहार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस सर्जरी की उच्च संख्या दर्ज की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रजनन आयु की महिलाओं के बीच उच्च स्वास्थ्य बीमा कवरेज दर्ज किया गया।

निजी अस्पतालों की भूमिकाः देशभर में दो-तिहाई ऑपरेशन निजी क्लीनिक या अस्पतालों में किए गए। यह प्रवृत्ति लाभ कमाने की मंशा का संकेत देती है।

3 से 7 जनवरी तक भारी बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट, सड़कें-हाईवे-स्कूल बंद

नेशनल डेस्क. पूरे देश में इन दिनों भीषण सर्दी की लहर चल रही है, और अधिकांश राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। इस महीने में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा बने रहने की संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग ने इस दौरान बारिश होने की भी आशंका जताई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 3 से 7 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश और गरज के साथ बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तीनों राज्यों में बर्फबारी और तापमान लाहौल स्पीति के ताबो में बर्फबारी के कारण न्यूनतम तापमान -14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, समदो में -9.3, कुकुमसैरी में -6.9, और कल्पा में -2 डिग्री तापमान रहा। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा चुका है, जिससे झरने जम गए और सड़कें ब्लॉक हो गईं। मौसम का असर जम्मू-कश्मीर में 4 से 6 जनवरी के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है।

पिता की मौत पर जश्नः श्मशान घाट पर डांस

लाश के सामने ढोल-नगाड़े और नोटों की गड्डियां उड़ी

नेशनल डेस्क. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने पिता की मौत पर श्मशान घाट पर डांस किया और बैंड बाजे के साथ अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

सुल्तानपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड में श्रीराम नाम के शख्स ने अपने पिता रामकिशोर मिश्रा की 80 साल की उम्र में मौत के बाद एक अनोखे तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। आमतौर पर मौत के समय घर में शोक का माहौल होता है, लेकिन श्रीराम ने बैंड बाजे और ढोल-नगाड़े के साथ जश्न मनाया। श्मशान घाट पर अंतिम यात्रा में श्रीराम और उसके दोस्त नाचते-गाते हुए पहुंचे, जहां ढोल की थाप पर नोटों की गड्डियां भी उड़ाईं।

इतना ही नहीं, श्रीराम ने तेरहवीं के दिन भी जश्न मनाया और परिवार के सदस्य और जानकारों को भोज कराया। जब श्रीराम से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, अंतिम विदाई रोते हुए नहीं, बल्कि नाचते-गाते हुए करनी चाहिए। रोने से आत्मा को तकलीफ होती है, और यह भी जीवन का उत्सव है, जिसे इसी तरह मनाना चाहिए।

यह घटना अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, जहां लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569